

03 दिल्ली-एनसीआर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली शाम पर दिवाली जैसा नजारा

06 गरीबी घटी, पर उत्सव का सफर बाकी

08 वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रामलला प्राण प्रतिष्ठा संपन्न

क्या दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार वाहन है या सरकार जानबुझ कर इनको जिम्मेदार ठहराती है? बड़ा सवाल :- संजय बाटला

हाईलाइट

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1997 में दिशा निर्देश दिए जिसके अंतर्गत दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों को पेट्रोल डीजल की जगह बिना प्रदूषण वाली सीएनजी वर्जन में परिवर्तन आवश्यक बताया गया था और साथ में यह भी बताया गया की भारत देश में यूरो 6 मानक आने पर पेट्रोल और डीजल से चालित वाहन भी प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे।

हम दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और जनता से पूछना/जानना चाहते हैं क्या सच में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण दिल्ली में चलने वाले वाहन है ?

संजय बाटला

नई दिल्ली । दिल्ली एनसीआर में जिस तरह प्रदूषण नियंत्रण में नहीं आ रहा और यहाँ रहने वाले निवासी उसकी मार से पीड़ित हैं और इसके कारण शारीरिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं के लिए जिम्मेदार क्या सच में सड़कों पर दौड़ते हुए वाहन है ? या राज्य सरकारें, वायु गुणवत्ता आयोग और भारत सरकार का इसके पीछे कोई और ही खेल है ?

आपकी जानकारी हेतु बता रहे हैं की मात्र एक हफ्ते के लिए सरकार द्वारा लागू ग्रेप 3 की बंदिश से सरकारी खजाने में कई करोड़ों रुपये आ जाते हैं जिसका सबूत कोई भी व्यक्ति आरटीआई द्वारा विभागों से मंगा कर देख सकता है, तो क्या कहीं सरकार इतना मोटा राजस्व वसूल करने की लिए ही तो वाहन के ऊपर प्रदूषण का ठीकरा नहीं फोड़ रही है ?

दूसरा प्रदूषण के नाम पर बार बार वाहनों पर पाबन्दी के कारण लोग ना चाहते हुए भी नया वाहन खरीदने को मजबूर हो रहे हैं उससे भी सरकार के राजस्व में मोटी रकम आ जाती है, कही साथ में यह भी कारण तो नहीं



वाहनों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने का ?

हम दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और जनता से पूछना/जानना चाहते हैं क्या सच में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण दिल्ली में चलने वाले वाहन है ? इस गंभीर विषय पर कुछ समय पहले टोलवा द्वारा गहन अध्ययन करवाया गया था और वाहन क्षेत्र से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों से परिचर्चा और गोष्ठी भी की गई थीं। अध्ययन के बाद जो बातें निकल कर सामने आई वह बहुत महत्वपूर्ण - और परिवहन विभाग से जवाब प्राप्त करने वाली हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1997 में दिशा निर्देश दिए जिसके अंतर्गत दिल्ली में व्यवसायिक वाहनों को पेट्रोल

डीजल की जगह बिना प्रदूषण वाली सीएनजी वर्जन में परिवर्तन आवश्यक बताया गया था और साथ में यह भी बताया गया की भारत देश में यूरो 6 मानक आने पर पेट्रोल और डीजल से चालित वाहन भी प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे, इसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के लिए सीएनजी अनिवार्य के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और सभी व्यावसायिक रूप से परिवहन क्षेत्र के वाहन मालिकों को अपने वाहनों को या तो सीएनजी किट लगवाना पड़ी थी या उन्हें नये सीएनजी चालित वाहन खरीदने पड़े थे। यहां सवाल सामने आता है जो प्यूल प्रदूषण मुक्त था तब उससे चलने वाले वाहन प्रदूषण कैसे फैला सकते हैं, या तो परिवहन

विभाग और अन्य सरकारी विभाग जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इससे अवगत कराया वह झूठ बोल रहे थे या आज जो सीएनजी से चलने वाले वाहनों से भी प्रदूषण है बोलते हैं वह झूठ बोल रहे हैं। साल 2020 से भारत देश में बिकने वाले वाहन और प्यूल यूरो 6 मानक है और नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूरो 6 मानक होना अनिवार्य कर दिया गया जो प्रदूषण मुक्त है * फिर भी राजधानी दिल्ली और आस पास के राज्यों में प्रदूषण का स्तर सबसे बुरा, आखिर क्यों ? क्या, परिवहन विभाग के आला अधिकारी मुख्य रूप से परिवहन आयुक्त जनता को इस पर अपना पक्ष बताने की कृपा करेंगे।

After market product range for all vehicle segments

2 Wheelers
3 Wheelers
Passenger Vehicles
Commercial Vehicles

जय माता दी

माँ महाकाली मोटर्स

(भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

सभी सी.एन.जी और डीजल वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक स्पीड गवर्नर एवं GPS (AIS 0140) उपलब्ध एवं लगाये जाते हैं।

H.O. प्लॉट नंबर 7, हिमगिरी एन्क्लेव, नजदीक बुराड़ी अर्थोस्ट्री, बुराड़ी, नई दिल्ली-110084

Email : mahakalimotors@rediffmail.com

Contact : off.- 9310034578, 9910234578

PRICOL LIMITED
Passion to Excel
109, Race Course, Coimbatore - 641 018, India.
0422-4336000
connect@pricol.com

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा दिल्ली प्रशासन और दिल्ली सरकार से अपील

कृप्या करके जनता के पैसों से नदियों को साफ मत कीजिए, बस इतना कर दीजिए की नदियों को गंदा करना बंद कर दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं नदियां स्वयं अपने आप को साफ कर जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल प्रदान करने लगेंगी। पेड़ मत उगाइए, बस पेड़ काटना बन्द कर दीजिए जो आप अपने विभागों के आला अधिकारियों के कहने पर कटवाते हो, हरियाली खुद हो जाएगी।

2024 में देश के हाईवे पर चालू हो जाएंगी 400 वे-साइड अमेनिटीज, शुरू हुई टेंडर की प्रक्रिया

परिवहन विशेष न्यूज

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश में 650 वे साइड एमेनिटीज स्थापित करने की घोषणा की है। मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार चार सौ वे साइड एमेनिटीज के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और कोशिश की जा रही है कि ये इस साल तक स्थापित हो जाएं। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। इस साल चार सौ से अधिक वे साइड एमेनिटीज यानी राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाओं युक्त विश्राम स्थल बन जाने के आसार हैं। इससे राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन सवारों की कठिनाइयां कम हो सकती हैं।

650 वे साइड एमेनिटीज स्थापित करने की घोषणा

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे देश में 650 वे साइड एमेनिटीज स्थापित करने की घोषणा की है। मंत्रालय



के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार चार सौ वे साइड एमेनिटीज के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और कोशिश की जा रही है कि ये इस साल तक स्थापित हो जाएं। वे साइड एमेनिटीज में पेट्रोल-डीजल पंपों के साथ ही चार्जिंग स्टेशन भी

बनाए जाने हैं ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को भी लंबे सफर के लिए चार्जिंग की सुविधा मिल सके।

प्रति 50 किलोमीटर पर इन केंद्रों की स्थापना की बात साइड एमेनिटीज के मामले में अभी

तक रफ्तार धीमी रही है, लेकिन अब इसमें तेजी लाने के लिए मंत्रालय कई स्तरों पर प्रयास कर रहा है। अधिकारी के अनुसार जैसे-जैसे एक्सप्रेसवे और हाईवे का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे वे साइड एमेनिटीज की जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाईवे पर प्रति पचास किलोमीटर पर इन केंद्रों की स्थापना की बात कहते रहे हैं।

एमेनिटीज में होंगी ये सुविधाएं इन एमेनिटीज में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं, जैसे कि फूड कोर्ट, शौचालय, चार्जिंग स्टेशन, कैफेटेरिया, विश्राम स्थल, बाजार आदि। यहां स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से स्थान बनाया जाएगा ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा सके।

अधिकारी के अनुसार वे साइड एमेनिटीज की स्थापना में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन कई मंजूरीयां जरूरी होने के कारण काम धीमा जरूर रहा है।

दिल्ली में इन वाहनों की एंट्री बैन, राजधानी के कई रास्ते; परेड रिहर्सल पर आई नई ट्रैफिक

23 जनवरी को दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले तक जाएगी। इस दौरान दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। इसके साथ ही सोमवार रात 11 बजे से परेड खत्म होने तक किसी भी भारी परिवहन या हल्के मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस परेड के लिए मंगलवार यानी 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। परेड रिहर्सल सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले पर समाप्त होगी। इस दौरान दिल्ली के कई रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी।

लाल तक जाएगी परेड

ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से उस हिसाब से घर से निकलने की सलाह दी है। बताया गया कि परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा चौराहे, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी।

रात 11 बजे से इन वाहनों पर रोक

इस दौरान सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार को रिहर्सल के अंत तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सोमवार रात 11 बजे से परेड खत्म होने तक किसी भी भारी परिवहन या हल्के मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश

की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एडवाइजरी का पालन करने का अनुरोध

दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया कि इन वाहनों को मंगलवार सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक केवल रिंग रोड पर आईएसबीटी-सराय काले खां और आईएसबीटी-कश्मीरी गेट के बीच चलने की अनुमति होगी। एडवाइजरी में मोटर चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और चौराहों पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। खास बात है कि इस दौरान दिल्ली में 15 फरवरी तक पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकोप्टर या विमान से पैर जॉंपिंग जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान प्रतिबंधित है।

अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क हब-एंड-स्पोक डिजाइन को लेकर कई बातें कहीं।

इंडियन रेलवे देगा टॉप क्लास सर्विस : अश्विनी वैष्णव

विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में एक साक्षात्कार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रौद्योगिकियों में स्विट्जरलैंड के साथ सीखने को लेकर बातें कहीं। पीटीआई न्यूज एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने स्विस् रेलवे के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है।

नई दिल्ली। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में एक साक्षात्कार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रौद्योगिकियों में स्विट्जरलैंड के साथ सीखने को लेकर बातें कहीं। पीटीआई न्यूज एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने स्विस् रेलवे के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है।

स्विट्जरलैंड से सीखेंगे रेलवे मैनेजमेंट

दरअसल, इस योजना के साथ भारतीय रेलवे हब, स्पोक मॉडल और



टर्नलिंग टेक्नोलॉजी के साथ उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को सीखेंगी।

अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क हब-एंड-स्पोक डिजाइन को लेकर कई बातें कहीं। इस मॉडल में, कई ट्रेनें ज्यूरिख जैसे केंद्रीय केंद्र पर इकट्ठी होती हैं।

इस सुविधा के साथ यात्रियों को एक ही समय में प्रस्थान करने वाली दूसरी ट्रेनों पर

आसानी से स्विच करने की सुविधा मिलती है।

अश्विनी वैष्णव ने स्विस् रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ बैठकों में सुरंग बनाने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया।

इस क्षेत्र में स्विट्जरलैंड की विशेषज्ञता की सराहना करते हुए उन्होंने दुनिया की सबसे लंबी 57 किलोमीटर लंबी गोथर्ड

सुरंग का हवाला दिया। अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड की अच्छी तरह से विकसित ट्रैक तकनीक की सराहना की।

भारतीय रेलवे की नई योजना

जापान की बुलेट ट्रेनों से प्रेरित मालूम हो हाल ही में भारतीय रेलवे ने जापान के 7-मिनट सफाई चमत्कार की तर्ज पर अपनी सफाई सेवा लॉन्च की। दरअसल, जापान में ट्रेनों को यात्रा के

अगले दौर की तैयारी के लिए आगमन के बाद रिकॉर्ड 7 मिनट में साफ किया जाता है।

ठीक इसी तरह भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए यह सफाई सेवा योजना अपनाई। 1 अक्टूबर, 2023 को 14 मिनट की सफाई चमत्कार के साथ भारतीय रेलवे ने अपना संस्करण लॉन्च किया था।

टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

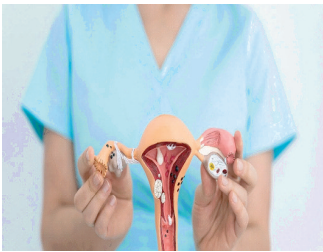
TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathiasanjaybathia@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ोदा दिल्ली 110042

इन्साइड



फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं। उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, न की इस पर खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की। सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उतेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है। आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताते जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपकी आदानी होने वाली है'

महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं ! महिला के बाहरी यौन अंग को लेंबिया मेजोरा कहा जाता है। यह यौनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो फोल्ड्स में मौजूद होती है। भीरी यौन अंग को लेंबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेंबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं।

आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं। फैला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं है, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं।

विभिन्न चरणों में समझे फ्रीमेल ऑर्गेज्म जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है। पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है। दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। क्लाइटोरिस को "फ्रीमेल पेनिंस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है। तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक बढ़ती है। अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है।

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं। इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गजम चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है। क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है।

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक
दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है। जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनाटॉमी को ध्यान में रखें। इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है।

**महिलाओं में होने वाली
हेल्थ से जुड़ी परेशानियां,
जिनके बारे में जानना है
बेहद जरूरी**

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेथ्स की संभावना अधिक होती है. यही नहीं, डिप्रेशन और एंजायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही हेल्थ कंडीशंस से जुड़े होते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडीशंस का समय पर महिना नहीं होता. पाता.

छात्राओं का बढ़ता यौन उत्पीड़न रोकें

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें। क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मिता की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए।

डा. वरिंदर भाटिया

देश के अनेक राज्यों के शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का यौन शोषण चिंताजनक बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में कोचिंग संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसको तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। आयोग ने कहा है कि हाल के सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर चिंतित है। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के मामले जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत हों और केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई हो। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) विधेयक 2012 (संशोधित विधेयक) संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। यौन उत्पीड़न कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमारी जानकारी के लिए, किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी लालच देकर अनौपचारिक रूप से दबाव बनाना भी यौन शोषण अपराध का हिस्सा होता है। कार्यस्थल पर अश्लील चित्र दिखाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधियों की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला के साथ अभद्रता करने का गलत गलौज करना भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मंदिर इसका अपवाद नहीं हो सकता है। ऐसी घटनाओं को तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत होती है परन्तु छात्राओं द्वारा



किन्हीं कारणों से इसको न बताने पर उनका शोषण बढ़ता जाता है। बेहतर है सरकारें छात्राओं से मिली इस सनकरी को गुप्त रख छद्म जांच करें और कार्रवाई करें। कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी से सामाजिक व्यकुलता बढ़ रही है। यौन शोषण का छात्राओं के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस मनुष्य का यौन शोषण हुआ होता है वह पूरी मानसता से नफरत करने लगता है। यह हर एक व्यक्ति केवल शोषण करने वाला ही दिखता है क्योंकि यह उसकी मानसिकता बन जाती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि वह यौन शोषण उसे बार-बार याद आते रहते हैं और उसको और ज्यादा मानसिक तकलीफ होती है जो उसके लिए बहुत कष्टदायक होती है, यह जिस तन लागे वोही जाने वाला स्थिति तब तब। आज सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले एक छात्र ऑडिट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों और विभागों में सर्वेक्षण किया गया। कुल 810 छात्र-छात्राओं ने सवालों के जवाब दिए। इसमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हर चार छात्राओं में से एक ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। यौन उत्पीड़न के 188 मामलों में 40 मामले शारीरिक उत्पीड़न के थे। उत्पीड़न के पांच में से एक मामला जबरदस्ती छूने या पकड़ने का था। उत्पीड़न के प्रत्येक पांच मामलों में एक कोशाल मीडिया पर ट्रोल करने या एक सांथ ला लिखित

वांटेंसोएप मैसैजों के जरिए उन्पीडन कर था।

जवाब देने वाले तकरीबन 80 प्रशिक्षण छात्र-छात्राओं ने परिसर में असुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाने की जिम्मेदार ठहराया। एफ़ा ऑफ़िट सरकारों की तरफ से सभी कॉलेजों को करवाया जाना चाहिए। सभी बालों तो सिर्फ छात्राएं ही नहीं, अमूमन सभी लड़कियों की लाइफ बहुत टकराती है। उन्हें हर कदम पर न जानने कितनी है। नजरों का सामना करना पड़ता है हर कदम पर उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की चिंता लगी रहती है। ऑफ़िस या स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, अब तो लड़कियां पर तक परफेक्ट नहीं हैं। आए दिन पित्त या भाव द्वारा भी रैप की खबरों से सोशल मीडिया भरा रहता है। ऐसे माहौल में आप भी समझ सकते हैं कि यौन उन्पीडन की वजह से लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों को यहां तक कि तथैव में महिला अध्यापकों का शिकार होना पड़ता है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो बेडरूम सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यह एक न हजम होने वाली सच्चाई हो सकती है। छात्राओं के यौन शोषण को लेकर विदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर छात्राओं का यौन उन्पीडन सबसे ज्यादा होता है। कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उन्पीडन किया जाना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में

महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है। वहां की कई यूनिवर्सिटीयों में ऐसी कोविड विद्यार्थियों पर नही है जिससे कर्मचारियों के विद्यार्थियों पर नही संबंध के लिए दबाव बनाने से रोका जा सके। इनका ही नहीं, ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त नियम नहीं हैं। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ और स्टूडेंट्स का ये हाल है तो फिर बाकी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। एक जमाने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्या का मंदिर समझा जाता था और आज अपने देश में भी इनमें से कुछ की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि अब इन्हें विद्या का मंदिर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसे बजटमान करें, ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए करें जिससे छात्रों के यौन शोषण के मामले दबे नहीं। छात्राओं का मायलै उन्टीडन शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से नहीं लें, क्योंकि हमारे पड़ताल दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कॉमिंग सेट्स में छात्राओं की अस्मत्त की सुरक्षा के क्या उपाय किए जा रहे हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई को उसका देने के लिए उन्हे सुरक्षित अकादमिक माहौल दिया जा सके। छात्राओं के हॉस्टल उनके लिए फिक्कने सुरक्षित हैं, यह वैरिफिकेशन जरूरी और तुरंत हो तो बेहतर है। छात्राओं को सुरक्षित करना ही होगा।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें
भूलने लगी हैं, तो 'मॉमी ब्रेन'
प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव



क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगती हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गईं कि आप वर के कमरे में आई या गाड़ी को चाबी हाथ में हैं और आप पूरे प्लैट में चाबी दूँदती रहीं? अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस्या नहीं है। दरअसल इस समस्या को 'मॉमी बेन' के नाम से जाना जाता है। वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन्म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के याददाश्त 2 क्षमता पर स्थाई असर पड़ता है।

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई माँ को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है। यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की जरूरतों को अपनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अहम होता है।

माँमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इरिटेटेड हो जाते हैं। आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एव स्ट्रप लाना बनाएं तो माँगी ब्रेन की समस्या से उबर सकती हैं।

लिस्ट बनाएं- इस समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस्ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प्लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें। इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा।

मसलन, आप अगर सुबह डॉट टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें। आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि।

पर्याप्त नाई जरूरी - नई मांओं की टयर तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रूटीन को फॉलो करना है कि आपकी नाई पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच्चे के साथ ही सोने और जागने की रूटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नाई आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दौं एक्स्ट्रा केथर - ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और ब्रेन गेम खेलें। ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेगा, इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो।

ज्यादा वजन भी बन सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह, इन तरीकों से करें बचाव

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के खतरे से खुद को बचाना है तो समय-समय पर अपनी जांच जरूर कराती रहें। इसके अलावा, जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में तनाव से दूर रहें, भरपूर आराम करें और रोजाना योग जरूर करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप इस खतरे से बच सकती हैं।

माँ बनने का अपना हर महिला देखती है। लेकिन कई महिलाओं में सेहत से जुड़ी समस्याओं के वजह से उनकी प्रेगनेंसी कठिनायों से भरी होती है। कई बार तो उनके लिए प्रेगनेंसी जोखिम बराह जाता है और इससे माँ और बच्चे दोनों की जान तक जा सकती है। इसी जोखिम को 'हाई रिस्क प्रेगनेंसी' कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 5,29,000 महिलाओं की मौत गर्भावस्था के दौरान इन खतरों की वजह से हो जाती है। इसकी वजह खराब सेहत, बदलती लाइफस्टाइल, खान पान में लापरवाही को माना जाता है। यही नहीं, कई बार ऐसी समस्याएँ किसी बीमारी या जेनेटिक डिजीज की वजह से भी हो सकती हैं।

हाईरिस्क प्रेगनेंसी की ये हैं बड़ी वजह



एनआईएच के मुताबिक अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे प्रेगनेंसी में रिस्क की समस्या हो सकती है। अगर महिला का वजन ज्यादा है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लेम्पसिया, गर्भकालीन मधुमेह, स्टिलबर्थ, न्यूरोल ट्यूब दोष और सिजेरियन

डिलीवरी की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से जन्म के समय नवजात में हृदय रोग का खतरा 15% तक बढ़ सकता है।

किशोरावस्था और 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था की वजह से प्रीक्लेम्पसिया और गर्भकालीन उच्च रक्तचाप का

खतरा बढ़ जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह बन सकता है। गर्भाशय में हुई कोई पुरानी सर्जरी की वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है। इसके अलावा, जुड़वा बच्चों और आविर्भाव द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया भी महिलाओं में रिस्क प्रेगनेंसी की वजह हो सकता है।

हाईरिस्कप्रेगनेंसीसेबचावकातरीका

अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो समय-समय पर अपनी जांच कराती रहें। इसके अलावा, प्रेगनेंसी में तनाव से बचें, भरपूर आराम करें, रोजाना योग ध्यान करें, फ्रेश हवा में बाँक पर जाएं, हेल्दी खान पान करें और डॉक्टर की संपर्क में रहें।

अयोध्या में विराजे रामलला... दिल्ली-एनसीआर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली शाम पर दिवाली जैसा नजारा, देखें तस्वीरें

परिवहन विशेष न्यूज

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देशभर में माहौल राममय हो गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि देशभर में दिवाली मनाई जा रही है। घर और मंदिरों में घाटों पर दीये जलाए जा रहे हैं। दिल्ली सहित आसपास के शहरों में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हो गए हैं।

नई दिल्ली/एनसीआर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देशभर में माहौल राममय हो गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि देशभर में दिवाली मनाई जा रही है। घर और मंदिरों में, घाटों पर दीये जलाए जा रहे हैं। दिल्ली सहित आसपास के शहरों में कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है।

अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यमुना वासुदेव चाए पर दीपोत्सव के दौरान अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति।

श्रीरामोत्सव के दौरान इंदिरापुरम की जयपुरिया सनराइज ग्रीन सोसायटी में दीये से लिखा जय श्रीराम।

अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी से अपने घर पर दीप प्रज्वलित करने को कहा था। इस अवसर पर शाम से लोगों ने घर पर दीये जाला शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने भी दीप प्रज्वलित किया है।

दिल्ली के कर्नाट प्लेस में जलाए गए दीप

बृजघाट पर जलाए गए दीप

दिल्ली सहित आसपास के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, हापुड़ में दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। पलवल के होडल के त्यागी मंदिर में भी दीये जलाए गए हैं। हापुड़ के बृजघाट में लगभग डेढ़ लाख दीये जलाए गए।

गुरुग्राम में दीप जलाते हुए, पटाखे भी फोड़ेंगे

ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी स्थित श्री राधा कृष्ण पार्क में भी 51000 दीये जलाए।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट गौर सिटी स्थित श्री राधा कृष्ण पार्क में भी 51000 दीये जलाए गए हैं। गाजियाबाद जिले भी लोग दीये जला रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं।

श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपों से जगमगाता दिल्ली का इस्कॉन मंदिर।

अयोध्या में उत्साह का माहौल

22 जनवरी 2024 दिन सोमवार यह भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन बन गया। अयोध्या में रामलला विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा की गई, जिसका उत्सव पूरे देश ने मनाया। रामलला प्राण-प्रतिष्ठा की खुशी में आज पूरी रामनगरी में दीवाली जैसा उत्सव है। अयोध्या में सरयू घाट पर दीप जलाकर प्राण-प्रतिष्ठा का जश्न मनाया जा रहा है।



पीएम मोदी ने किया संबोधित

पीएम मोदी ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद देश विदेश से आए करीब 7000 से अधिक लोगों को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि रामलला की मूर्ति के अनावरण का पल न केवल विजय का, बल्कि विनम्रता का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि राम भारत के विचार हैं। ये

राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत का विधान हैं। राम व्यापक हैं। राम चेतना भी हैं। राम चिंतन भी हैं। राम वर्तमान हैं।

राम अनंतकाल हैं। हमारे रामलला अब टैंट में नहीं रहेंगे। अब रामलला दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमें श्रीराम का मंदिर मिला है। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर राष्ट्र खड़ा हुआ है।

महापौर ने किया सुमित रंगा पार्क का नामकरण

परिवहन विशेष। एसडी सेटी।

एमसीडी वार्ड-24 के ई-ब्लॉक सेक्टर-1, रोहिणी, अर्वातिका स्थित सेंट्रल पार्क को स्वर्गीय सुमित रंगा के नाम पर राम सोमवार को मेयर शैली ओबेरॉय ने उद्घाटन कर अपनी खजाली अर्पित की। इस भव्य उद्घाटन समारोह में विधायक महेंद्र गोयल, क्षेत्रीय पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सौलंकी, आरडब्ल्यूए प्रेसीडेंट आनंद कोशिक, स्वर्गीय सुमित रंगा के पिता राम कुमार रंगा, वार्ड अध्यक्षत ईनाउमेश गुप्ता, समाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र सौलंकी, और निगम अधिकारी, उद्यान विभाग के कर्मचारी, समेत इलाके के सैकड़ों की संख्या में महिला एंव पुरुष भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रिटाला वार्ड के विधायक महेंद्र गोयल ने स्वर्गीय सुमित रंगा को अपने भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चाईना मांजे ने नौजवान सुमित रंगा की वक्त से पहले जान ले ली। इसका



हमें बेहद दुख है ईश्वर से प्रार्थना है कि उसे प्रभु उसे शांति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि रंगा परिवार की समाज के प्रति समर्पित सेवा भावना से हम खासे प्रभावित हैं। जैसे

ही सेंट्रल पार्क के नामकरण का प्रस्ताव आया, तो पार्षद समेत हमने महापौर शैली ओबेरॉय से पार्क का नाम स्वर्गीय सुमित रंगा के नाम पर रखने की अपील की। मेयर



ने इसकी अनुमति दे दी। और आज उन्होंने स्वंम पार्क के नाम पर उद्घाटन भी कर दिया। पार्षद पुष्पा की ओर से सुरेंद्र सौलंकी ने मेयर को बताया कि वार्ड-24 के पांच

पार्क को नया स्वरूप देने का फैसला लिया है। पर्यावरण, और क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर जल्द ही इन पार्कों में विकास के काम शुरू कर दिए जाएंगे।

सोने-चांदी के तारों से कढ़ाई, टंड से बचाएंगी खास शाल; किसने तैयार किया भगवान रामलला का वस्त्र?

मूल रूप से उग्र के अंबेडकर नगर के और दिल्ली में पिछले 20 वर्ष से रहने वाले मनीष त्रिपाठी पिछले 40 दिनों से अयोध्या में ही राम के वस्त्र तैयार करने में रमे हुए थे। वस्त्र तैयार कर खुद को सौभाग्यशाली बताने वाले डिजाइन मनीष त्रिपाठी इसे प्रभु राम का आशीर्वाद व पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मानते हैं।

नई दिल्ली। रामलला का शुभ वस्त्र तैयार कर खुद को सौभाग्यशाली बताने वाले डिजाइन मनीष त्रिपाठी इसे प्रभु राम का आशीर्वाद व पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मानते हैं। वह कहते हैं कि वस्त्र तैयार करवाने वाले भी वहीं हैं। वह रामलला से बात करते थे और उन्होंने ही बताया कि उन्हें कैसे वस्त्र

चाहिए। क्योंकि यह केवल वस्त्र तैयार करने तक का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के आस्था का मामला था।

शिलान्यास के मौके पर भी तैयार किया था वस्त्र

चक्रवर्ती राजा दशरथ के पांच वर्षीय पुत्र व भगवान विष्णु के अवतार का वस्त्र तैयार करना उनके वंश की बात नहीं थी। वह बताते हैं कि वस्त्र तैयार करने के लिए वह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व पंडितों के संपर्क में रहे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनपर विश्वास किया। इसके पूर्व में मनीष ने तीन वर्ष पूर्व शिलान्यास के अवसर पर भी प्रभु राम का वस्त्र तैयार किया था।

तब उन्हें उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा यह जिम्मेदारी दी गई थी। मूल रूप से उग्र

के अंबेडकर नगर के और दिल्ली में पिछले 20 वर्ष से रहने वाले मनीष त्रिपाठी पिछले 40 दिनों से अयोध्या में ही राम के वस्त्र तैयार करने में रमे हुए थे। इसके लिए डिजाइनों और कढ़ाई करने वाले 15 सदस्यीय टीम भी वहीं है। राम लला के वस्त्र में धोती, कमरबंद व दो पटुकाएं हैं।

टंड के लिए तैयार किया गया शाल

साथ ही टंड है तो शाल भी ओढ़ाया गया है, जिसे काशी के विशेष पितांबरी से तैयार किया गया है, जबकि कढ़ाई में सोने व चांदी के तारों का इस्तेमाल किया गया है। वस्त्र में पदम चक्र व गदा की कढ़ाई की गई है। वह कहते हैं कि प्रभु के लिए वस्त्र तैयार करते समय रंगों का चयन तथा विग्रह के एक ही पत्थर से तैयार होने को भी विशेष ध्यान में रखा था, क्योंकि वस्त्र

पहनाने में मूर्ति को खरोच भी बड़ा नुकसान होता।

IPL व BCCI के लिए किया काम

मनीष त्रिपाठी ने राष्ट्रीय फैशन प्रीयोगिकी संस्थान (निफ्ट) से पढ़ाई की है। पूर्व में उन्होंने आईपीएल व बीसीसीआई के क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ कई फिल्मी अभिनेता और प्रसिद्ध लोगों के लिए परिधान डिजाइन किए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ ही काम किया है, लेकिन काम से संतुष्टि अब उन्हें रामलला का वस्त्र तैयार करने में मिली है।

इसके लिए वह अपने पिता हरीओम त्रिपाठी व प्रेम त्रिपाठी के साथ ही पत्नी तन्मय द्विवेदी को भी योगदान देते हैं। कहते हैं कि उनपर परिवार का विश्वास और भरोसा था, इसलिए भी वह यह हिम्मत कर सके।



राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसाद देने वाली वेबसाइट को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जनता की धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित करने वाली और खुद को अयोध्या में श्रीराम मंदिर (Shri Ram Temple) में समारोह प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद को वितरित करने के अधिकारिक मंच के रूप में प्रचारित करके उन्हें धोखा देने वाली एक वेबसाइट के संचालन को निर्लंबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावना आहत करके पैसे कमाना चाहते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जनता की धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित करने वाली और खुद को अयोध्या में श्रीराम मंदिर (Shri Ram Temple) में समारोह प्राण प्रतिष्ठा के प्रसाद को वितरित करने के अधिकारिक मंच के रूप में प्रचारित करके उन्हें धोखा देने वाली एक वेबसाइट के संचालन को निर्लंबित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा वेबसाइट के खिलाफ एक मुकदमे से निपटने के दौरान देखा कि प्रतिवादी मंच खादी ऑर्गेनिक के नाम से काम कर रहा था, जो कि भ्रामक रूप से वादी के समान था। पीठ ने वेबसाइट को सभी भ्रामक इंटरनेट मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया।

धार्मिक भावना आहत करके पैसे कमाना चाह रहे

पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी व्यक्ति और कंपनी जनता की धार्मिक मान्यताओं और भक्ति का शिकार करके और वादी की सद्भावना का उपयोग करके कंपनी को धन हस्तांतरित करने में उन्हें धोखा देकर अभिषेक कार्यक्रम पर एकाधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अदालत ने वेबसाइट के पंजीकृत डोमेन नाम के संचालन को निर्लंबित कर दिया।

बेच रहे थे ये चीजें

केवीआईसी ने अदालत को बताया कि प्रतिवादी मंच धार्मिक समारोह के आयोजन को लेकर विभिन्न उत्पादों जैसे परिधान, संग्रहणीय वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, घरेलू मंदिर, गंगाजल व अन्य आवश्यक सामान की पेशकश कर रहा था। यहां तक कि अपनी मुफ्त प्रसाद पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय योगदान भी मांग रहा था।

केवीआईसी ने अदालत को बताया कि वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुफ्त में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रसाद (Ram Mandir Pran Pratishtha) प्राप्त करने के इच्छुक लोग वहां दिए गए एक फार्म को भरकर और 51 रुपये का शुल्क देकर अपना आईड दे सकते हैं।

वादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी को उसके पंजीकृत खादी चिह्न का दुरुपयोग करने और यह गलत धारणा देने का कोई अधिकार नहीं है कि यह श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबद्ध था, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कर रहा है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। अदालत ने प्रतिवादी को खादी ऑर्गेनिक चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया और मुकदमे पर समन जारी किया।

नोएडा में एयर इंडिया के कर्मों की हत्या करने वाले दो शूटर गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए शूटरों ने 19 जनवरी को नोएडा में गैंगस्टर परवेश मान के भाई सूरज मान की गोली मार कर हत्या कर दी थी। सोमवार को पुलिस के साथ एनकाउंटर में दोनों ने छह राउंड फायरिंग की जिनमें दो गोलियां एक इंसपेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। पुलिसकर्मियों द्वारा आत्मरक्षा में गोलियां चलाने पर दोनों के पैरों में दो गोलियां लगने से वे घायल हो गए।

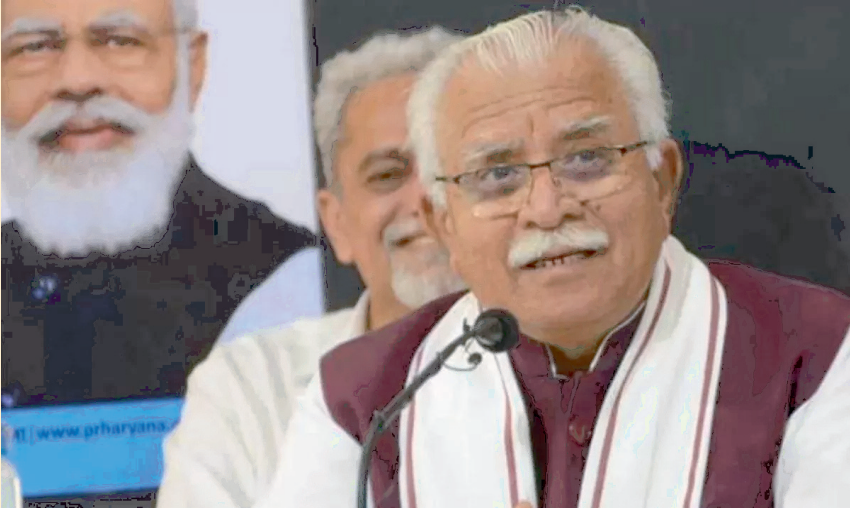
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई-कपिल उर्फ कल्लू खेड़ा व गोपी गिरोह के दो शूटर को सराय काले खां बस अड्डा के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर बीते 19 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 104 में कपिल के विरोधी गैंगस्टर परवेश मान के भाई सूरज मान की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

कई सदस्यों की गैंगवार में हो चुकी हत्या

हाल के वर्षों में परवेश मान व कपिल के परिवार के कई सदस्यों की गैंगवार में हत्या हो चुकी है। विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच शालिनी सिंह के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शूटरों के नाम कुलदीप (भज्जपुरा) व अब्दुल कादिर (बिजनौर) है। दोनों ने लॉरेंस बिश्नोई-जितेंद्र उर्फ गोपी व कपिल उर्फ कल्लू खेड़ा व नीरज बवाना-परवेश मान गिरोह के बीच लंबी प्रतिद्वंद्विता के कारण सूरज मान की हत्या की।

घटना के दौरान सूरज मान अपने आवास के पास स्थित एक जिम में व्यायाम करने जा रहा था, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने उसपर अंधाधुंध गोलियां चला मौके से भाग गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान सूरज मान की मौत हो गई थी। सूरज मान, परवेश मान का भाई था, जो दिल्ली में मकोका के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और नीरज बवाना गिरोह का प्रमुख सदस्य है।

गुरुग्राम को 191 करोड़ का तोहफा देंगे सीएम मनोहर लाल करीब 50 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास



परिवहन विशेष न्यूज

डीसी निशांत कुमार यादव ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम में करीब 31.5 करोड़ की लागत से तैयार 13 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा करीब 160 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 29 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 10 से 11 बजे तक रहेगा।

गुरुग्राम। सीएम मनोहर लाल 24 जनवरी को जिला गुरुग्राम के लिए वरुंडाली लगभग 191 करोड़ रुपये से अधिक की 42 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर नगर निगम, मानेसर क्षेत्र में एचएसआईआईडीसी ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव

इंद्रजीत सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे।

डीसी ने किया कार्यक्रम स्थल का दौरा

वहीं ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही विधायक सत्यप्रकाश जरावता, सुधीर सिंगला, राकेश दौलताबाद तथा विधायक संजय सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिला में यह परियोजनाएं शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सड़क एवं जल प्रबंधन पर केंद्रित हैं। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम में करीब 31.5 करोड़ की लागत से तैयार 13 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा करीब 160 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 29 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 10 से 11

कुमकुम के घर जन्मे राम, डॉक्टर बोलीं- जय श्रीराम

ख़ास बात यह है कि डॉक्टर प्रियंका ने उसका नाम राम रखते हुए पूरे लेबर रूम में जय श्री राम के नारे लगाए और मिठाई बांटी गई। अभी तक मिली सूचना के अनुसार जिला महिला अस्पताल में कुल पांच में से दो महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोनी में हुए कुल आठ प्रसव के सापेक्ष पांच महिलाओं ने बेटों को जन्म दिया है।

गाजियाबाद। कुमकुम के घर जन्मे राम डॉक्टर बोलीं- जय श्रीराम। जी है जिला महिला अस्पताल में 22 जनवरी की सुबह को सबसे पहली डिलिवरी बम्हटा गांव के रहने वाले अजय शर्मा की पत्नी कुमकुम की की गई है। डॉक्टर प्रियंका द्वारा की गई सामान्य डिलीवरी के तहत उसको बेटा पैदा हुआ है।

ख़ास बात यह है कि डॉक्टर प्रियंका ने उसका नाम राम रखते हुए पूरे लेबर रूम में जय श्री राम के नारे लगाए और मिठाई बांटी गई।

अभी तक मिली सूचना के अनुसार जिला महिला अस्पताल में कुल पांच में से दो महिलाओं ने बेटे को जन्म दिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोनी में हुए कुल आठ प्रसव के सापेक्ष पांच महिलाओं ने बेटों को जन्म दिया है।

'22 जनवरी को ही हो डिलीवरी'

मुग़दन्नगर में तीन और मोदीनगर में दो प्रसव होने की सूचना है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी 10 से अधिक प्रसव हुए हैं।

अयोध्या में आज आयोजित होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते जिले भर में पिछले 10 दिन से अनेक महिलाएं चिकित्सकों के पास जाकर अनुप्रेषण कर रही थीं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को ही की जाए, लेकिन अधिकांश को निराशा ही हाथ लगी।

एसीएमओ डॉक्टर चरन सिंह ने बताया कि आज सरकारी अस्पतालों में होने वाले प्रसव के तुरंत बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और जननी सुरक्षा योजना का फंड संबंधित महिला के खाते में तुरंत रिजली कराया जाएगा।

रेस लगाकर कैश पुरस्कार जीतने का मौका, फैमिली फिटनेस फन (F3) कंपनी 4 फरवरी करेगी 'Noida 10K Run' का आयोजन

अगर आपकी फिटनेस अच्छी है और लंबी वॉक/रेस लगा सकते हैं तो आपको नोएडा में अच्छा इनाम पाने का मौका मिलने जा रहा है। नोएडा स्थित फैमिली फिटनेस फन (F3) इवेंट मैनेजमेंट कंपनी 'Noida 10K Run' का आयोजन कराने जा रही है। इसका मोटो है कि रूआप सपने देखें, हम पूरा करते हैं! रू कंपनी ने अपने कुशल प्रबंधन के साथ दो मेगा इवेंट सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। कंपनी अपना अगला इवेंट ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क वी स्थित जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में 4 फरवरी, 2024 को कर रही है। इस आयोजन के जरिये लोगों में स्वस्थ जीवन शैली और विश्व कैसर दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

डिकेथलॉन, मैक्स हेल्थ केयर, जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल और जागरण डॉट कॉम (Jagran.com) सहित कई प्रमुख स्पॉन्सर इस इवेंट के प्रतिभागियों में शामिल हैं। नोएडा 10K रन में कई सुविधाएं होंगी। अलग-अलग फिटनेस स्तर वाले प्रतिभागियों के लिए इसमें 5 K/10K/फन रन/वॉक विभिन्न टेकअवे के अलावा प्रतिभागियों को रोमांचक नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। यह पुरस्कार 10K वर्ग के शीर्ष 5 पुरुष/महिला विजेता और 5K श्रेणी के 3 पुरुष/महिला विजेताओं को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा।



एनसीआर /विविध विशेष

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, वाहनों के आपस में भिड़ने से एक की मौत; दो घायल

निरंजन मार्जनी

पीछे से आ रही कार ने उनकी कैब में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कैब अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची। जहां चिकित्सकों ने मयंक को मृत घोषित कर दिया जबकि महिला व कार चालक को अस्पताल में भर्ती कर लिया।



मोदीनगर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को कार और कैब की भिड़ंत हो गई। जिसमें कैब चालक की मौत

हो गई, जबकि कार चालक व एक महिला को हालत अस्पताल में गंभीर बनी है।

देहरादून से दिल्ली के लिए मिली बुकिंग

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत

वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पण करने के बाद जमानत मिल गई है। मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था। अधिवक्ता की तरफ से भूपेश की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई।

ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को समर्पण करने के बाद जमानत मिल गई है। मामले में पुलिस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उनको तलब किया था।

अधिवक्ता की तरफ से भूपेश की सरेंडर अर्जी दाखिल की गई। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जमानत दे दी है। भूपेश समर्थकों के साथ

सोमवार को गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय पहुंचे थे।

प्रचार करने आए थे नोएडा

अधिवक्ता रजनीश यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के चुनाव प्रचार में नोएडा आए थे। भूपेश ने पंखुड़ी पाठक व अन्य कांग्रेसियों के साथ प्रचार किया था। इसी बीच पुलिस की तरफ से महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया।

कोर्ट ने किया था तलब

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उन्होंने जमानत कराई। पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने भूपेश को तलब किया। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पंखुड़ी पाठक, अनिल यादव न्यायालय पहुंचे।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रजनीश ने कोर्ट में दलील दी कि भूपेश बघेल को राजनीति द्वेष में फंसाया गया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी



वजह से कोई बीमारी नहीं फैली है। इस तर्क पर, कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ता कपिल भाटी,

पुणेंद्र यादव, राहुल भाटी, सचिन कसाना, जयकरण शर्मा समेत कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।

अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत की आर्थिक विकास दर जा सकती है 10 प्रतिशत के पार

प्रह्लाद सबनानी

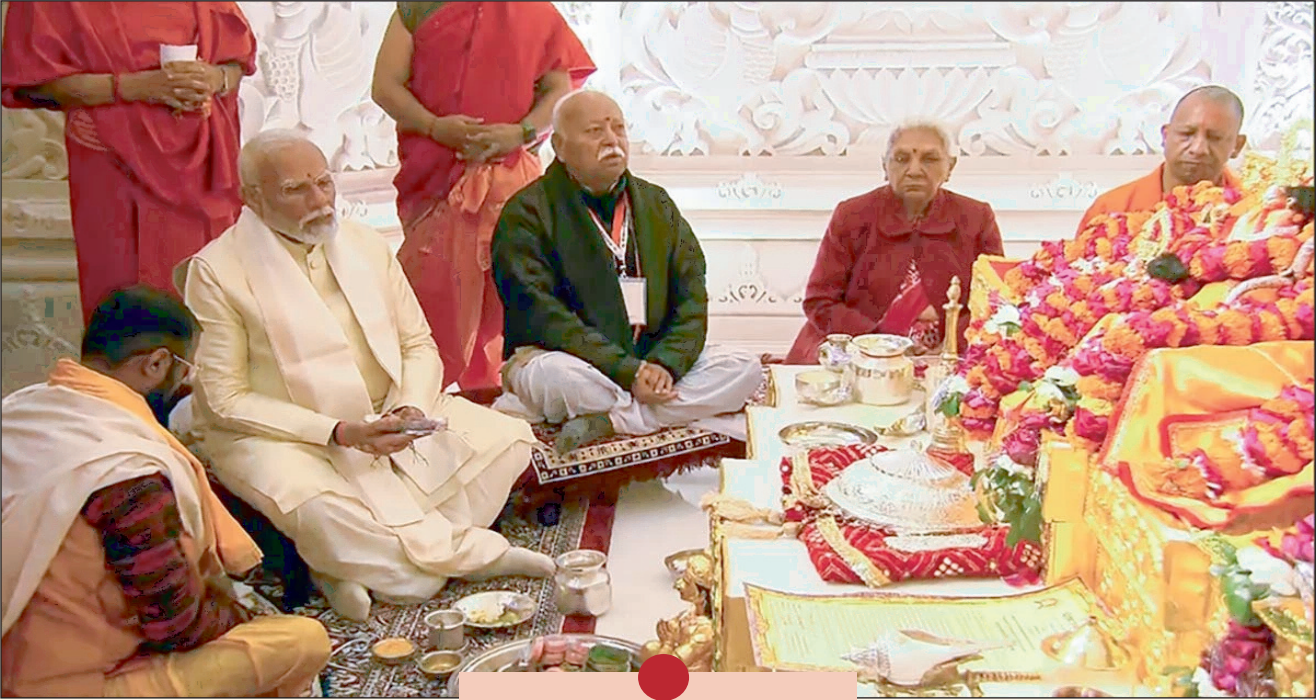
मुद्रा स्फीति की दर वर्ष 2013 में 10 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई है। इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है और उनके व्यय करने की क्षमता बढ़ी है। देश में डिजिटल क्षेत्र का तो जैसे कायाकल्प ही हो गया है।

किसी भी देश में आर्थिक विकास को अतुलनीय गति देने में केवल 10 वर्ष का समय बहुत कम माना जाता है। इतिहास गवाह है कि कई देशों को आर्थिक विकास की रफ्तार को गति देने में दशकों लग जाते हैं। चीन ने वर्ष 1980 का आसपास अपने देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए थे परंतु इनका परिणाम दशकों बाद दिखाई दिया था, लगभग यही स्थिति अन्य देशों की भी रही है। परंतु, भारत ने पिछले केवल 10 वर्षों के दौरान अर्थ के कई क्षेत्रों में पूरे विश्व को राह दिखाई है।

भारत में आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा गया है क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति देने में आधारभूत ढांचे का विकसित अवस्था में होना अति आवश्यक माना जाता है। भारत में वर्ष 2013 में केवल 4,100 किलोमीटर रेल्वे लाइन का विद्युतीकरण किया जा सका था जो वर्ष 2023 में बढ़कर 28,100 किलोमीटर के हो गया है। राष्ट्रीय हाईवे भी वर्ष 2014 के 25,700 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2023 में 53,700 किलोमीटर के हो गए हैं और भारत में वर्ष 2014 में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 148 हो गए हैं। इस प्रकार के आधारभूत ढांचे को विकसित करने से भारत में रेल्वे ट्रेक, राष्ट्रीय हाईवे सहित सड़क मार्ग एवं एयरपोर्ट की उत्पादकता बढ़ी है एवं पेट्रोल, डीजल की खपत में कमी होकर देश में पर्यावरण की स्थिति को सुधारने में भी सहायता मिली है।

मुद्रा स्फीति की दर वर्ष 2013 में 10 प्रतिशत थी जो वर्ष 2022 में घटकर 4.7 प्रतिशत हो गई है। इससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है और उनके व्यय करने की क्षमता बढ़ी है। देश में डिजिटल क्षेत्र का तो जैसे कायाकल्प ही हो गया है। वर्ष 2016 में डिजिटल व्यवहार देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 4.4 प्रतिशत ही हो पा रहे थे जो वर्ष 2023 में बढ़कर 76.1 प्रतिशत से भी अधिक होने लगे हैं। इसी प्रकार, देश में भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनियों (आईआईटी) की संख्या वर्ष 2014 में 16 से बढ़कर वर्ष 2023 में 23 हो गई है, भारतीय मेडिकल कंपनियों (आईआईएम) की संख्या वर्ष 2014 के 13 से बढ़कर वर्ष 2023 में 20 हो गई है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2013 में 385 से बढ़कर वर्ष 2023 में 693 हो गई है और अखिल भारतीय मेडिकल साइंस संस्थानों (एमएस-एआईआईएमएस) की संख्या वर्ष 2014 में 7 से बढ़कर वर्ष 2023 में 25 हो गई है। कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत में महत्वपूर्ण संस्थानों को भारी संख्या में विकसित किया गया है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्ष 2014 में 28,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर था जो वर्ष 2023 में दुगने से भी अधिक होकर 60,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है। विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2013 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 2,200 करोड़ अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया था जो वर्ष 2023 में दुगने से



भी अधिक होकर 4,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है।

अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के ऋणः सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि आगे आने वाले समय में भारत के लिए यह अनुपात 100 के स्तर को पार कर सकता है, यदि ऐसा होता है तो यह भारत के आर्थिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। परंतु, भारत में निगमों का औसत ऋणः सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2015 के 65 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2023 में 50 प्रतिशत के स्तर पर आ गया है और, उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2028 तक केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का ऋणः सकल घरेलू उत्पाद अनुपात भी कम होकर 80 प्रतिशत के निचले स्तर पर नीचे आ जाएगा।

केंद्र सरकार पर लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार के संस्थानों को बेचा जा रहा है। जबकि अब केंद्र सरकार के विभिन्न 25 संस्थानों ने पिछले एक वर्ष के दौरान अपने निवेशकों की पूंजी में 100 प्रतिशत से अधिक का संवर्धन किया है। विशेष रूप से आईआरएफसी ने 437 प्रतिशत, इरकोन ने 343 प्रतिशत, आरवीएनएल ने 321 प्रतिशत, कोचीन शिपार्ड ने 247 प्रतिशत, पीएफसी ने 250 प्रतिशत, रैलटेल ने 247 प्रतिशत, आईटीआई ने 245 प्रतिशत, हुडको ने 245 प्रतिशत का संवर्धन निवेशकों के निवेश में पिछले एक वर्ष के दौरान किया है। आज न केवल विदेशी संस्थागत निवेशक और भारतीय संस्थागत निवेशक बल्कि खुदरा निवेशक भी केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में निवेश करने पर अधिक भरोसा जता रहे हैं।

और, फिर अब तो अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी 2024 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघचालक श्री मोहन जी भागवत एवं पूज्य संत मंडल के सानिध्य में सम्पन्न की जा चुकी है।

केंद्र सरकार पर लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार के संस्थानों को बेचा जा रहा है। जबकि अब केंद्र सरकार के विभिन्न 25 संस्थानों ने पिछले एक वर्ष के दौरान अपने निवेशकों की पूंजी में 100 प्रतिशत से अधिक का संवर्धन किया है। विशेष रूप से आईआरएफसी ने 437 प्रतिशत, इरकोन ने 343 प्रतिशत, आरवीएनएल ने 321 प्रतिशत, कोचीन शिपार्ड ने 247 प्रतिशत, पीएफसी ने 250 प्रतिशत, रैलटेल ने 247 प्रतिशत, आईटीआई ने 245 प्रतिशत, हुडको ने 245 प्रतिशत तक का संवर्धन निवेशकों के निवेश में पिछले एक वर्ष के दौरान किया है।

संस्कृति का पालन करने वाले नागरिक भी भारी संख्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन करने हेतु अयोध्या आएंगे। इससे, भारत में धार्मिक पर्यटन नई ऊंचाईयों को छूने जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंचेंगे। यह संख्या शीघ्र ही 3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचा प्रत्येक श्रद्धालु यदि 2500 रुपए की खर्च करता है तो केवल अयोध्या की स्थानीय अर्थव्यवस्था में 25000 करोड़ रुपए शामिल होंगे। यह श्रद्धालु अयोध्या जाते हुए वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा में बांके बिहारी मंदिर आदि में भी दर्शन हेतु अवश्य आएंगे। इस प्रकार, वाराणसी एवं मथुरा की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खुराक प्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है। इस प्रत्यक्ष खुराक का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर लगभग 5 गुना चक्रीय असर भी हो सकता है जो अंततः भारत के आर्थिक विकास में ही जुड़ने जा रहा है। धार्मिक पर्यटन से यातायात, होटल, स्थानीय स्तर पर निर्मित विभिन्न उत्पादों जैसे क्षेत्रों में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते हैं। इससे भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। विश्व में कई देशों यथा, स्विजरलैंड, इटली, फ्रान्स, अमेरिका, युएई, आदि ने पर्यटन के बलवृत्त पर अतुलनीय आर्थिक विकास किया है एवं अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित श्रेणी की अर्थव्यवस्था बना दिया है। इसी प्रकार अब अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अब भारत भी इस श्रेणी के देशों में शामिल होने जा रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की दर 10 प्रतिशत के पार जा सकती है।

सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन eC3: प्राइस, फीचर्स और ड्राइविंग रेंज के मामले में कौन बेहतर? खरीदने से पहले जान लीजिए

दोनों ही इलेक्ट्रिक कार बेहतरीन रेंज के साथ पेश की जाती हैं। हालिया लॉन्च टाटा पंच ईवी 25 kWh बैटरी पैक प्रदान किया गया है। यह सिंगल चार्जिंग में 315 किमी की रेंज देने में सक्षम है। जबकि इसके प्रतिस्पर्धी के तौर पर आने वाली Citroen eC3 में मिलने वाले बैटरी पैक की क्षमता 327 किमी रेंज देने की है।

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक सेगमेंट तेजी से विस्तार कर रहा है और इस सेगमेंट में वाहन निर्माता कंपनियां भी खूब वाहन लॉन्च कर रही हैं। ग्राहक पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों को कम तरजोह दे रहे हैं। ऐसे में हम यहां आपके लिए दो इलेक्ट्रिक कारों का पूरा कंपेरिजन लेकर आए हैं। लेख में आपको टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन eC3 के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

बैटरी और रेंज में कौन बेहतर

दोनों ही इलेक्ट्रिक कार बेहतरीन रेंज के साथ पेश की जाती हैं। हालिया लॉन्च टाटा पंच ईवी 25 kWh बैटरी पैक प्रदान किया गया है। यह सिंगल चार्जिंग में 315 किमी की रेंज देने में सक्षम है। जबकि इसके प्रतिस्पर्धी के तौर पर आने वाली Citroen eC3 में मिलने वाले बैटरी पैक की क्षमता 327 किमी रेंज देने की है। बता दें टाटा पंच ईवी दो वेरिएंट में आती है जबकि सिट्रोएन ईवी को सिंगल वेरिएंट में



पेश किया जाता है। फीचर्स का कंपेरिजन इंटीरियर और फीचर्स के मामले में दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो पंच ईवी Citroen eC3 से बेहतर दिखाई पड़ती	है। टाटा पंच ईवी में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। इसमें में वेंटीलेटेड सीट, एक नया स्टीयरिंग व्हील, वैकल्पिक सनरूफ,	ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो वाइपर, प्रोजेक्टर एलईडी की सुविधा मिलती है। सिट्रोएन eC3 में एपल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.2 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट	क्लस्टर, डुअल टोन डैशबोर्ड और फ़ैब्रिक सीट प्रदान की गई हैं। Tata Punch EV vs Citroen eC3 की कीमत टाटा पंच ईवी की एक्सशोरूम कीमत	10.99 लाख से शुरू होती है और Citroen eC3 की कीमत 11.61 लाख रुपये से शुरू होती है। पंच ईवी के टॉप वेरिएंट की कीमत 15.49 लाख रुपये तक जाती है तो वहीं eC3 का टॉप वेरिएंट	12.99 लाख रुपये में आता है। यह कीमते एक्सशोरूम के हिसाब से हैं। अब आप अपने बजट और पसंद के अनुसार किसी भी कार का चयन कर सकते हैं।
--	--	--	---	--	---

ऑडी के ये छल्ले 4 पॉपुलर ब्रांड्स को करते हैं रिप्रजेंट, जानिए Logo के पीछे की रोचक कहानी

Audi के लोगो में शामिल किए गए 4 रिंग अलग-अलग वाहन निर्माता कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस यूनियन में नीचे दी गई 4 कंपनियां शामिल थीं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑटो यूनियन ने कारों मोटरसाइकिलों और वैन का उत्पादन किया लेकिन 1950 के दशक के मध्य में इसे वित्तीय और श्रम समस्याओं का सामना करना पड़ा। समय के साथ Audi का लोगो बदल गया।

नई दिल्ली। दुनिया भर की पॉपुलर कार निर्माता कंपनियों में शुमार Audi को लेकर हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। क्या आपने कभी ऑडी के लोगो में चार जुड़ी हुई रिंगों के पीछे के अर्थ के बारे में सोचा है? अगर आपका जवाब 'नहीं' है, तो हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं।

'audi के लोगो में 4 छल्ले ही क्यों?'

Audi के लोगो में शामिल किए गए 4 रिंग अलग-अलग वाहन निर्माता कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस यूनियन में नीचे दी गई 4 कंपनियां शामिल थीं।

29 जून 1932 को Auto Union AG बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ सैक्सोनी की पहल पर ऑडीवेक, होर्चवेक और जस्कोपाउर



मोटरनवेकें जे.एस. रासमुसेन एजी (डीकेडब्ल्यू) का विलय हुआ था। विलय के बाद ऑटो यूनियन एजी जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी मोटर वाहन निर्माता थी। कंपनी के प्रतीक में चार इंटरलॉकिंग रिंग शामिल थे, जिसका उद्देश्य चार संस्थापक कंपनियों की अविभाज्य एकता का प्रतीक था।

समय के साथ बदला लोगो

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑटो यूनियन ने कारों, मोटरसाइकिलों और वैन का उत्पादन किया, लेकिन 1950 के दशक के मध्य में इसे वित्तीय और श्रम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑटो यूनियन को 1958 में डेमलर-बेंज द्वारा खरीदा गया था और 1964 में वोक्सवैगन को बेच दिया गया।

VW के अधिग्रहण के तुरंत बाद, ऑटो

यूनियन ने ऑडी नाम से कारों की बिक्री शुरू कर दी। इसके 1969 में इसने एक अन्य कार निर्माता, एनएसयू का अधिग्रहण कर लिया। कंपनी तब ऑडी एनएसयू ऑटो यूनियन एजी बन गई।

इसके बाद VW Group ने अपनी इसप्रीमियम कार निर्माता को Audi का नाम देते हुए लोगो तो भी काफी सरल कर दिया।

लॉन्च हुई Maruti Brezza माइल्ड हाइब्रिड, माइलेज में पहले से हो गई है बेहतर; जानिए कीमत और फीचर्स



Maruti Brezza माइल्ड हाइब्रिड को एक बार फिर से भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया है। बता दें पिछले साल निर्माता ने जुलाई महीने में SUV के माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट पर रोक लगा दी थी। लेकिन एक बार फिर से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें पहले की तुलना में माइलेज को बेहतर कर दिया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी ब्रेजा एसयूवी के टॉप MT वेरिएंट को माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक के साथ फिर लॉन्च किया है। अब यह गाड़ी 1.5-लीटर K15C माइल्ड-हाइब्रिड इंजन ZXI MT और ZXI+ MT ट्रिम्स में उपलब्ध है। बता दें पिछले साल निर्माता के द्वारा जुलाई महीने में SUV के माइल्ड-हाइब्रिड मैनुअल वेरिएंट पर रोक लगा दी थी। लेकिन एक बार फिर से इसे लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

कितनी है कीमत

माइल्ड-हाइब्रिड फीचर अब ब्रेजा के टॉप-स्पेक ZXI और ZXI+ मैनुअल वेरिएंट पर पेश किया गया है और इनकी कीमतें क्रमशः 11.05 लाख रुपये और 12.48 लाख रुपये हैं। पेश की गई गाड़ी माइलेज

विगत मॉडल की तुलना में और भी अधिक हो गया है। टॉप-स्पेक ब्रेजा के लिए माइलेज का आंकड़ा 17.38 किमी/लीटर से बढ़कर 19.89 किमी/लीटर हो गया है। जो दिखाती है कि कंपनी ने इस पर काम किया है।

इंजन और पावर में क्या बदला

गाड़ी में फीचर्स और अन्य विशेषताओं में कोई परिवर्तन खासतौर से देखने को नहीं मिला है। यह मॉडल 1.5-लीटर K15C 4-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित है। इस इंजन की क्षमता 103 hp की अधिकतम शक्ति और 136.8 Nm का पीक टॉर्क पैदा उत्पन्न करने की है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। बता दें एसयूवी सीएनजी संस्करण में भी पेश की गई है।

पिछले साल हुई गाड़ी की अच्छी बिक्री

विगत वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि इस गाड़ी को ग्राहकों के द्वारा खूब प्यार दिया गया है। कैलेंडर वर्ष 2023 में ब्रेजा ने टाटा पंच, हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और महिंद्रा स्कार्पियो जैसे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर भारत में सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी के रूप में अपना स्थान हासिल किया था। मारुति ने पिछले वर्ष के दौरान ब्रेजा की 1,70,600 इकाइयों की बिक्री की थी।

Hero Mavrick भारतीय बाजार में आज मारेगी एंट्री, लॉन्च से पहले जानिए ये 5 जरूरी बातें

Hero Motocorp की ओर से 23 जनवरी 2024 को Mavric को पेश किया जाएगा। कंपनी द्वारा ऑनलाइन टीज किए गए कुछ डिजाइन एलीमेंट में मोटरसाइकिल को एक शानदार लुक देने वाला बड़ा फ्यूल टैंक शामिल है।

Harley-Davidson X440 पर आधारित होने के बावजूद ये डिजाइन के मामले में एक रोडस्टर है। All-new Hero Mavrick को एक स्ट्रीटफाइटर के रूप में पेश किया गया है।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero Motocorp की ओर से 23 जनवरी 2024 को Mavric को पेश किया जाएगा। घरेलू ब्रांड का ये अगला उत्पाद हाले-डेविडसन

X440 पर आधारित है। आइए, इससे संबंधित 5 जरूरी बातों के बारे में जान लेते हैं।

स्ट्रीटफाइटर डिजाइन

कंपनी द्वारा ऑनलाइन टीज किए गए कुछ डिजाइन एलीमेंट में मोटरसाइकिल को एक शानदार लुक देने वाला बड़ा फ्यूल टैंक शामिल है। Harley-Davidson X440 पर आधारित होने के बावजूद ये डिजाइन के मामले में एक रोडस्टर है।

अलॉय व्हील

All-new Hero Mavrick को एक स्ट्रीटफाइटर के रूप में पेश किया गया है। इसमें कई अपडेट भी किए गए हैं। लॉन्च के बाद, यह घरेलू दोपहिया निर्माता की नई फ्लैगशिप मोटरसाइकिल होगी।

सिग्नेचर एलईडी लाइट

Hero Motocorp ने पहले ही आगामी Mavric की सिग्नेचर एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट को टीज कर दिया है, जिसमें ब्रांड को दर्शाने वाला 'H' मोटिफ मिलता है। ये हेडलैंप पूरी तरह से एलईडी है, जबकि टर्न इंडिकेटर्स और टेललाइट भी एलईडी यूनिट की विशेषता के साथ आते हैं।

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

नई हीरो मैवरिक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आती है। उम्मीद है कि ये स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आएगी और मोटरसाइकिल व राइडिंग डायनामिक्स के बारे में डिटेल्ड इनफार्मेशन डिस्प्ले करेगा।

Harley-Davidson X440 मोटरसाइकिल पर आधारित होने के बावजूद, new Hero Mavrick अपने विशिष्ट स्टाइलिंग एलीमेंट और विशेषताओं के साथ आती है। इसमें अलॉय व्हील भी शामिल है, जो इसे X440 से अलग करता है।

नया पावरट्रेन

Hero Mavrick 440 अपने Harley-Davidson समकक्ष से ही इंजन प्राप्त करेगी। उम्मीद है कि आने वाली मोटरसाइकिल में शक्तिशाली 440 सीसी इंजन होगा, जो X440 में काम करता है। यह इंजन 6-स्पीड ट्रांसमिशन से लैस होगा। हालांकि, हीरो मोटोकॉर्प ने औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि कंपनी इंजन और गियर में बदलाव करेगी।



गरीबी घटी, पर उत्सव का सफर बाकी



डा. जयंतीलाल भंडारी

युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दे रही कमियों को दूर करना होगा, वहीं उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ नए स्किल्स सिखाए जाने होंगे।

हाल ही में 15 जनवरी को नीति आयोग की तरफ से वैश्विक मान्यता के मापदंडों पर आधारित बहुआयामी गरीबी इंडेक्स (एमपीआई) पर दस्तावेज जारी किया गया है। इस इंडेक्स को निकालने के लिए बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन जैसी सुविधाओं पर आधारित 12 विभिन्न मानकों-पोषक तत्व, बच्चे की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा व बैंक खातों को शामिल किया गया है। इस दस्तावेज के मुताबिक सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की बहुआयामी गरीबी कम करने में अहम भूमिका रही है। वित्त वर्ष 2013-14 में देश की 29.17 प्रतिशत आबादी एमपीआई के हिसाब से गरीब थी। अब वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11.28 प्रतिशत लोग एमपीआई के हिसाब से गरीब रह गए हैं। इन नौ सालों में 17.89 प्रतिशत लोग यानी करीब 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आए हैं। [विश्व बैंक ने दिन में 180 रुपये से कम कमाने वालों को गरीबी रेखा से नीचे कहा है।] गौरलब्ध है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरप्रदेश में पिछले नौ सालों में 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़, मध्यप्रदेश में 2.30 करोड़ तो राजस्थान में 1.87 करोड़ लोग एमपीआई मानकों के हिसाब से गरीबी से मुक्त हुए हैं। इस हिसाब से अब लगभग 15 करोड़ लोग एमपीआई आई मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। ऐसे लोगों को संस्था बिहार में सबसे ज्यादा 26.59 फीसदी, झारखंड में 23.34 फीसदी, उत्तरप्रदेश में 17.40 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 11.71 फीसदी, राजस्थान में 10.77 फीसदी, तेलंगाना में 3.76 फीसदी, हिमाचल में 1.88 फीसदी, तमिलनाडु में 1.48 फीसदी, केरल में 0.48 फीसदी है। इन सबके सामने अभी भी बहुआयामी गरीबी से बाहर आने की चुनौती बनी हुई है। सरकार ने 2030 तक देश के ऐसे सभी नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर करने का लक्ष्य रखा है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के दस्तावेज के मुताबिक सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले पोषण अभियान व एनीमिया मुक्त भारत अभियान से स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त आन्नद, स्वच्छ ईंधन



के लिए उच्चवर्गीय योजना, सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, पेजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन व जल-धन खाती की सुविधा आदि से लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में खासी मदद मिली है। खासतौर से गरीबों के सांस्कृतिककरण में करीब 51 करोड़ से अधिक जनधन खातों (जे), करीब 134 करोड़ आधार कार्ड (ए) तथा करीब 118 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं (एम) की शक्ति वाले जैम से सुगठित बेमिसाल डिजिटल ढांचे की असाधारण भूमिका रही है। इसी शक्ति के बल पर देश के गरीब लोगों के खातों में सीधे आर्थिक राहत हस्तांतरित हो रही है। इसके साथ-साथ वर्ष 2020 से गरीबों व कमजोर वर्ग के 80 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क छाद्यान वितरण ने भी गरीबों के सांस्कृतिककरण में अहम भूमिका निभाई है। ज्ञातव्य है कि सरकार के द्वारा पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को इस माह जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों यानी 2028 तक मुफ्त अनाज देने के सिलसिले को जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

इस परिप्रेक्ष्य में यहां विगत 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की उल्लेखनीय है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबों 2015-2016 के मुकाबले 2019-2021 के दौरान 25 फीसदी से घटकर 15 फीसदी आ गया है। एशिया पैसेफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में जहां करीब 37 हजार रुपए थी, वहीं वर्ष 2022 में बढ़कर करीब 2 लाख रुपए हो गई है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष

बहुत दुनिया के विभिन्न सामाजिक सुस्था के वैश्विक संगठनों के द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी घटाने में भारत में लागू के खास सुस्था की जोरदार सहायता की गई है। आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पेपर में कहा गया है कि सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम ने कोविड-19 की वजह से लगाए गए लोकडाउन के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। और इससे अत्यधिक गरीबों में भी कमी आई है। वस्तुतः खाद्यान्न के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँचे सुरक्षित खाद्यान्न भंडारों के कारण ही देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण वे गरीबों के दलदल में फँसने से बचाया जा सका। यद्यपि देश में एक ओर गरीबों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएँ मसलत सामुदायिक रसोई, वन नेशन व राशन कार्ड, उच्चला योजना, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबों के स्तर में कमी लाने और स्वास्थ्य व भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायता मिली है। लेकिन अभी भी बहुआयामी का सामना कर रहे करीब 15 करोड़ से अधिक गरीबों को सरकार के लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2030 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए बहुआयामी गरीबों को कम करने से संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे कार्यन्वयन की दिशा में अभी बहुत अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि यद्यपि गरीबों के सशक्तिकरण के साथ देश में प्रतिव्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी भारत दुनिया

के उन प्रमुख 10 देशों में शामिल है, जहाँ बाते 20 वर्षों में लोगों की आय में असमान इजाफा हुआ है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि गरीब लोगों को मुफ्त अनाज के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे। इतना ही नहीं, देश की तेजी से बढ़ती आबादी के तहत गरीब वर्ग की नई आबादी की खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक खाद्यान्न उत्पादन के रणनीतिक प्रयत्न भी जरूरी होंगे।

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि जनकल्याण के मद्देनजर लोगों को रेवडियां बांटने जैसा अभियान आगे नहीं बढ़े। ऐसी लोक लुभावन

गरीबी से लड़ाई में सहायक बन सकें और जो गरीब लोगों को निजी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकें। उन्मिच्छ रूप से नीति आयोग के द्वारा जारी गरीब आयायमी गरीबी में कमी प्रस्तुत करता हुआ इंडेक्स अभी भी उत्सर्ग ममाने लक्ष्य पर पहुँच नहीं है। भारत को अभी भी निम्न आय वाला देश माना जाता है। विभिन्न वर्गों की प्रति व्यक्ति आय में संतुलित वृद्धि से अधिक लोग गरीबी के दायरे से बाहर आये और गरीबी जीवन बेहतर होगा। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि विकास की प्रक्रिया और गरीबी उन्मूलन में देश के कुछ प्रदेश बहुत पीछे छूट गए हैं। इन राज्यों के समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना होगा। इसके साथ-साथ सरकार की व्यक्ति को भी नए सिरे से न्यायसंगतता के मद्देनजर मूल्यांकित करते हुए इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्या अभी भी उन लोगों को भी एक समान राहत और नकद हस्तान्तरण किया जाए जो बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आ चुके हैं। चौकी कोविड-19 के बाद बहुआयामी गरीबी को दूर करने के लिए इस वर्ग के युवाओं में डिजिटल शिक्षा की जरूरत बढ़ गई है और इसकी अहमियत रोजगार में भी बढ़ गई है, ऐसे में गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके सृजने के लिए ऐन समय सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दे रही कमियाँ को दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें कौशल प्रशिक्षण के साथ नए सिस्तेम सिखाए जाने होंगे। ऐसे विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से जहाँ देश में बहुआयामी गरीबी में और कमी लाई जा सकेगी, वहीं आय असमानता को कम करने में भी मदद मिल सकेगी।

आज अनमोल घड़ी है।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक
पुनरोत्थान का स्थापना-दिवस है।
स्थूल रूप से कहा जाए, तो अयोध्या
में प्रभु राम के मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा
की तारीख है। अयोध्या तो हमेशा
प्राणवर्धनी रही है। उसकी चेतना और
स्पंदन में 'देवत्व' बसा है। अयोध्या
भारत की ही नहीं, सनातन के
आस्थावानों की आध्यात्मिक
राजधानी है। जहाँ सरयू माता है,
देवत्व का वास है, वहाँ से श्रीराम
कहाँ जा सकते हैं? भौतिक वनवास
उपने मानव-काल का एक दौर था।
सांप्रदायिकता और सियासत ने
अयोध्या को दिखावटी तौर पर
अभिशापन किया था। निध्वंश था,
अक्रमण था, विदेशी लुटेरों ने
कब्जे किए थे और मंदिर को मस्जिद
बनाने का दुस्साहस किया था,
लेकिन सरयू मां जीवित थी, तो
श्रीराम कण-कण में क्यों नहीं बसे
थे? अदृश्य और ओझल होना भी
देवत्व था, प्रभु राम की लीला थी,
एक और अग्नि-परीक्षा थी, लिहाजा
हमारे आराध्य तो अयोध्या में ही थे।
यह कथन सांस्कृतिक तौर पर उचित
नहीं है कि हमारे राम अयोध्या लोटे
हैं। वनवास से अयोध्या लौटे हैं।
अयोध्या और आराध्य एकत्व के
भाव में निहित हैं। बैराग भगवान
विष्णु ने मानव-रूप में जन्म
अयोध्या के राज-परिवार इक्ष्वाकु
वंश में लिया था, लेकिन उनका
अवतरण वैश्विक रहा है। करीब 55
देशों में प्रभु राम की मान्यता है। आज
भी अमरीका के करीब 1100 मंदिरों
में 'रामोत्सव' मनाया जा रहा है।
उसके भौतिकतावादी शहर भी
'राममय' हैं और आपस में 'जय
सियाराम' के उद्घोष के साथ एक-
दूसरे का अभिवादन करते हैं। ब्रिटेन
के 500 मंदिरों में 'श्रीराम
विजयोत्सव' मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री 'रामायण का पाठ'
जाकर 'श्रीराम का पाठ' सुन
सकते हैं। नीदरलैंड्स सुरुज देश में
'राम मंदिर के चित्र' वाले डाक
टिकट जारी किए गए हैं। यूरोप के
कई देश भी 'राममय' हैं। इसका
स्पष्ट निष्कर्ष है कि इतने व्यापक हैं

राम। भारत की प्रत्येक देशा में राम आराध्य हैं और 350 से अधिक 'रामायण' सृजित की गई हैं। राम के लिए जितना महत्त्व अयोध्या का है, उतना ही 'रामेश्वरम्' का है।

बहरहाल अयोध्या के राम मंदिर में आराध्य की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही 492 साल लंबी प्रतीक्षा, पीढ़ियों की अनवरत लड़ाई और कुर्बानियों, राजनीतिक विरोधाभासों, अदालती प्रणालियों और कुतर्कों के दौर समाप्त हो रहे हैं और धर्मनिपेक्षता का मूल्य भाव लिए श्रीराम स्थापित हुए हैं। यह प्रभु राम और उनकी देवीय सृष्टि का ही प्रभाव है कि लगातार नास्तिक भाव वाले राजनता और राजनीतिक दल आज राम को स्वीकार रहे हैं, शंकराचार्यों की महत्ता स्थापित कर रहे हैं और 22 जनवरी के बाद कभी भी राम मंदिर जाकर दर्शन करने की बात कह रहे हैं। यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र, आस्था और आराध्य की असीम, अनंत, अनन्तर, अहीन विजय है। बेशक गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और असुरी वृत्तियाँ आदि सार्वकालिक और स्थूल समस्याएँ हैं। देश की बेरोजगारी दर 17-18 फीसदी तक रही है। मुद्रास्फीति की दर 13-14 फीसदी तक बढ़ी है। देश का सोना तक बेचे की नौबत आ गई थी। डॉलर मुद्रा भंडार मात्र एक अरब डॉलर तक रह गया था। अमेरिका और हाल ही में अफ़ाक़त समुद्र हैं और भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सवाल हमसे रहेंगे। खलनायक और हमसे चेहरें चेमु राम वाले त्रेता युग में भी मौजूद थे। उनके अवतार का एक महान लक्ष्य असुरों का समापन भी था। हम दोनों युगों की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि युगों की संक्षिप्त विवेचना कर रहे हैं कि समस्याएँ शाश्वत हैं। स्थूल समस्याएँ और सांस्कृतिक पहचान अलग-अलग मुद्दे हैं। राम मंदिर इन समस्याओं को नजरअंदाज कर नहीं बनाया जा रहा है। आम आदमी धर्म की निष्ठा रहा है और 'राम-दीपावली' के जश्न में भी डबा है।

संपादक की कलम से

अयोध्या में ही राम

आज अनमोल घड़ी है।
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक
पुनरोत्थान का स्थापना-दिवस है।
स्थूल रूप से कहा जाए, तो अयोध्या
में प्रभु राम के मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा
की तारीख है। अयोध्या तो हमेशा
प्राणवंत रही है। उसकी चेतना और
स्पंदन में 'देवत्व' बसा है। अयोध्या
भारत की ही नहीं, सनातन के
आस्थावानों की आध्यात्मिक
राजधानी है। जहाँ सरयू माता है,
देवत्व का वास है, वहाँ से श्रीराम
कहाँ जा सकते हैं? भौतिक वनवास
उपने मानव-काल का एक दौर था।
सांप्रदायिकता और रियासत ने
अयोध्या को दिखावटी तौर पर
अभिशापन किया था। निध्वंश था,
अतिक्रमण था, विदेशी लुटेरों ने
कब्जे किए थे और मंदिर को मस्जिद
बनाने का दुस्साहस किया था,
लेकिन सरयू मां जीवित थी, तो
श्रीराम कण-कण में क्यों नहीं बसे
थे? अदृश्य और ओझल होना भी
देवत्व था, प्रभु राम की लीला थी,
एक और अग्नि-परीक्षा थी, लिहाजा
हमारे आराध्य तो अयोध्या में ही थे।
यह कथन सांस्कृतिक तौर पर उचित
नहीं है कि हमारे राम अयोध्या लोटे
हैं। वनवास से अयोध्या लौटे हैं।
अयोध्या और आराध्य एकत्व के
भाव में निहित हैं। बैराग भगवान
विष्णु ने मानव-रूप में जन्म
अयोध्या के राज-परिवार इक्ष्वाकु
वंश में लिया था, लेकिन उनका
अवतरण वैश्विक रहा है। करीब 55
देशों में प्रभु राम की मान्यता है। आज
भी अमरीका के करीब 1100 मंदिरों
में 'रामोत्सव' मनाया जा रहा है।
उसके भौतिकतावादी शहर भी
'रामयम' हैं और आपस में 'जय
रियाराम' के उद्घोष के साथ एक-
दूसरे का अभिवादन करते हैं। ब्रिटेन
के 500 मंदिरों में 'श्रीराम
विजयोत्सव' मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री रक्षा सुनक भी मंदिर
जाकर 'रामायण का पाठ' सुन
सकते हैं। नीदरलैंड्स सुरुज देश में
'राम मंदिर के चित्र' वाले डाक
टिकट जारी किए गए हैं। यूरोप के
कई देश भी 'रामयम' हैं। इसका
स्पष्ट निष्कर्ष है कि इतने व्यापक हैं

राम। भारत की प्रत्येक देशा में राम आराध्य हैं और 350 से अधिक 'रामायण' सृजित की गई हैं। राम के लिए जितना महत्त्व अयोध्या का है, उतना ही 'रामेश्वरम्' का है।

बहरहाल अयोध्या के राम मंदिर में आराध्य की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही 492 साल लंबी प्रतीक्षा, पीढ़ियों की अनवरत लड़ाई और कुर्बानियों, राजनीतिक विरोधाभासों, अदालती प्रणालियों और कुतर्कों के दौर समाप्त हो रहे हैं और धर्मनिपेक्षता का मूल भाव लिए श्रीराम स्थापित हुए हैं। यह प्रभु राम और उनकी देवीय सृष्टि का ही प्रभाव है कि लगातार नास्तिक भाव वाले राजनता और राजनीतिक दल आज राम को स्वीकार रहे हैं, शंकराचार्यों की महत्ता स्थापित कर रहे हैं और 22 जनवरी के बाद कभी भी राम मंदिर जाकर दर्शन करने की बात कह रहे हैं। यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र, आस्था और आराध्य की असीम, अनंत, अनन्तर, अहीन विजय है। बेशक गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और असुरी वृत्तियाँ आदि सार्वकालिक और स्थूल समस्याएँ हैं। देश की बेरोजगारी दर 17-18 फीसदी तक रही है। मुद्रास्फीति की दर 13-14 फीसदी तक रही है। देश का सोना तक बेचे की नौबत आ गई थी। डॉलर मुद्रा भंडार मात्र एक अरब डॉलर तक रह गया था। अमेरिका और हाल ही में अफ़ाक़त समुद्र हैं और भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सवाल हमसे रहेंगे। खलनायक और हमसे चेहरें चेमु राम वाले त्रेता युग में भी मौजूद थे। उनके अवतार का एक महान लक्ष्य असुरों का समापन भी था। हम दोनों युगों की तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि युगों की संक्षिप्त विवेचना कर रहे हैं कि समस्याएँ शाश्वत हैं। स्थूल समस्याएँ और सांस्कृतिक पहचान अलग-अलग मुद्दे हैं। राम मंदिर इन समस्याओं को नजरअंदाज कर नहीं बनाया जा रहा है। और आदमी धर्म की निष्ठा रहा है और 'राम-दीपावली' के जश्न में भी डूबा है।

राय

हिमाचल में कूड़े की तोहमत

जहाँ कभी भी शक्ति की स्मृति का प्रारूप बना करता था, वह शिमला आज देश में 188वें स्थान पर लड़खड़ा रहा है। पुराने प्रदेश को छवि में राष्ट्र का स्मृति का संरक्षण-2023 हम को दे रहा है। यह शहर व्यवस्था का नाकारापन है तो पर्वतीय शक्ति परिरक्षण के खिलाफ नागरिक समाज का अवरोधन भी इस विलक्षण होता है। आखिर हमारे शहर हैं किस तरह की वरिष्ठा स्मृति के नाम पर नागरिक समाज का व्यवहार तथा अपने शहर के प्रति वफादारी के बाजार नियंत्रण शक्ति के साथ हमें कूड़े को तोहमत बन रहे हैं तो इसलिए कि हमारे लिए हर कर्तव्य ज्ञान से बचाव है। आचार्य यह कि कूड़ेदान का नाम भी नागरिक ज्ञान नहीं चाहता और ऊपर से जौन शैली को हकीकत में हमें खुद कूड़ेदान बनने जा रहे हैं। जौन अकेले हो या समूहों में, अपने ही श्रेष्ठ से पीछा छोड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर शहर का कचरा पक्की घर से नहीं, बल्कि हर दुकान, हर स्टेशन, हर होटल, कंफ़ाण और हर मॉल से भी पर्यटन है। ऐसे में अगर व्यापार मंडल व टैक्सि, टैरल तथा नैकन एसोसिएशन भी प्रयास करें तो स्मृति को मुक्ति को शक्ति मिलेगी। सारी टूरिज्म इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि स्मृति इसकी पहली दृष्टि है, इसी परिप्रेक्ष्य में हिमाचल सरकार को ग्रीन टैक्स का विस्तार तथा इसे पुनः प्रतिभाषित करना होगा, ताकि इसका इस्तेमाल प्रदेश को प्रदूषणमुक्त करें। स्मृति केवल मुक्ति नहीं और अगर इसे मुक्ति मानें तो इसके पार्टनर जोड़ने पड़ेंगे स्मृति का एक नाम है और न ही ईमान, बल्कि जौन की संसत में भविष्य की जरूरत है।

जिस तक हिमाचल के शहरीकरण को नजरअंदाज किया गया, उसकी नतीजा यह कि अब हमारे जोन के मानदंडों के लिए प्रतिक्रिया में लोगों हैं। इसी दौरान चले ही हमने शहरीकरण के मानक पर नए एंग्रेज ग्रामीण योजना कानून को स्वीकार किया, लेकिन हम इसकी शक्ति अख्तियार नहीं की। किसी भी शहर को विकास में इतना न होना कि इसकी परिधि में जीवनशैली असाधारण न हो। नतीजतन शहरी शक्ति को बाधपास करते हुए हमने शहरीकरण के कब्रगाह पैदा कर लिए। पहाड़ों का एक प्राकृतिक जल निकासी सिस्टम रहा है, लेकिन इमारतों के दस्तूर में हमने इसे भी बर्बाद कर दिया। हमारे पास खड्डें, नालें और नदियाँ नहीं हैं, लेकिन हमने इन्हें भी कुदुदा बना दिया। हम आज तक हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों में जीना नहीं सीखे। शहरों में जनसुविधाएँ, होटलिंग कैपेसिटी, अनवरत प्लानिंग तथा सुखद बाधाएँ के लक्ष्य ही तय नहीं हुए। नतीजतन हर शहर आपत में फंसा है। अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य में अनुपातित समाज साबित नहीं हो रहे हैं, तो इसका एक पहलू सरकार से भी संबंधित है। सत्कारी शहरीकरण को बर्बाद करने से कतारती नहीं है या बचपनीय प्राधान्यों में उत्तर-दूढ़ने की कोशिश तक नहीं कर सकती। यही वजह है कि शहरी निकाय आज तक अपना आर्थिक ढांचा विकसित नहीं कर पाया। अगर स्मार्ट सिटी के नजराने में धर्मशाला-शिमला को उष्ण मिली, तो सत्कारी ने इसे समल करने के बजाय इन्हें सियासी प्रहसन बना दिया। इंदौर अगर लगातार स्वच्छ शहर बना रहा है, तो इसके कारण समझने नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने शहर को ढांचा, व्यवस्था और परिकल्पना दी, तो इंदौर ने खुद में आर्थिक तत्परकी का जन्म पैदा किया। इसके बिल्कुल उलट हिमाचल के शहर न तो आर्थिक रूप से खुद पर विश्वास कर रहे हैं और न ही नागरिक समाज कर अदायगी के नगर समूहगत होता है। बेशक जयराम सरकार ने तीन नए नगर निगमों का गठन करके प्रदेश में इनकी संख्या पाँच तक पहुँचा दी, लेकिन न तो इन्हें कानून सम्मत और आर्थिक रूप से संपन्न करने की कोशिश हुई। किसी भी नगर निगम में वास्तव परंतु पर न तो नियुक्तियाँ हुई और न ही इनकी स्थापना के लिए वांछित अधोसंरचना को धन प्राप्त हुआ। स

कुछ साल पहले एक अति उत्साही, ऊर्जावान तथा आशा भरोसे पूर्ण सेल्फी व्हाइट अब लोकोत्तरे लगा है। उसकी हालत अब घर के अप्रासंगिक हो चुके बुजुर्गों की तरह हो गई है, जिन्हें स्थिर और सामान्य हालत में केवल दिखना-होना है। आरंभ में यह सेल्फी व्हाइट सेल्फी इंटरमिनेशन का जीता जागता उदाहरण हुआ करता था। लोग इसके बगल में खड़े होते ही दृष्ट प्रतीति हो जाते थे। सेल्फी व्हाइट पहले ढाल की तरह, किसी दीवार की तरह लोगों की रोशनी में अपना चेहरा भी देख लेता था। अब सेल्फी पहचान एक बिछोने की तरह है। लोग अपने नेताओं से मिल नहीं पाते। लोकतंत्र से दूर होते नेताओं के बोझ में एक सेल्फी व्हाइट ही तो है जो खुद में लोकतंत्र बटोर रहा है। दरअसल सेल्फी स्टैंड अब लोकतंत्र स्टैंड या नेता की स्टैंड

पोषित हो जाना चाहिए
 ताकि इस बहाने से हमारा
 देश भविष्य के लोकतंत्र
 का प्रणेता बना जाए। यह पहला-पहला सेल्फी
 प्वाइंट है, लिहाजा सेवा भाव में हमेशा सेल्फ
 लेस रहा है। जिसने इसकी बांह पकड़ी, उसके
 साथ खड़ा हो गया और जिसने टांग तो खड़ी उसके
 साथ भी खड़ी हो गया। सेल्फी प्वाइंट ही अब
 ऐसा उपाय बचा है, जो देश से न तो कोई
 अवकाश मांगता है और न ही यह आंकड़ देता है
 कि आज तक आंकड़ों में कितने लोगों को सफल
 और कितनों को खुद के साथ जोड़ पाया है।
 दरअसल सेल्फी प्वाइंट ने बातों-बातों में देश के
 80 करोड़ लोगों को मुम्त के राखने के साथ
 सेल्फी लेने का अंदाज सिखा दिया। सरकार का
 मुम्त राखन दरअसल सेल्फी प्वाइंट ही तो है।

શવ સંવાદ-27

खींच लो जितनी हिम्मत है। अनाज को आज तक ये शकियाव नहीं कि उसके साथ सेल्फी खींचने वाला किताब फट्टेहाल है। अनाज भी अगर परिवारवादी हो जाता, तो सिर्फ किसान के साथ ही उसकी सेल्फी होती, लेकिन यहाँ तो हाथ में उसकी मुन्तखोरी बाँधने वाले नेताओं को यह भी मालूम नहीं कि कृषि उत्पादन की सेल्फी लेना आज तक संभव नहीं हुआ।

सेल्फी स्टैंड अब तेजी से विकसित होने की समृद्धि है। एक सेल्फी स्टैंड ही आपको किसी का मुरीद बना सकता है। देश को मुरीद बनाने का फाँसूला आ गया। हर जगह एक सेल्फी स्टैंड और इसमें प्राण फँकाता नेता का चित्र सभी को

मुरीद बना रहा है। वृक्ष को प्राण प्रतिष्ठा में हमारे बुद्धिजीवी को एक स्थायी भ्रम रहा है कि उसके कारण ही कई अन्य सोच पाते हैं। वह आजकल अपने प्राण समेट कर अयोध्या पहुँच चुका है। सेल्फी रैटेंड के बाजार की तरह बुद्धिजीवी की यह मह मुगालात है कि उसके साथ सेल्फी की वैल्यू बढ़ जाती है। तभी उसने देखा ठीक उसके सामने लगभग टूट चुका सेल्फी रैटेंड अपने बचे-खुचे दाँत निकालकर उस पर हंस रहा है। पहली बार बुद्धिजीवी को देखकर कोई सेल्फी रैटेंड खुश था। बुद्धिजीवी को लगा कि अयोध्या में अगर सेल्फी फ्लाइट उसे देखकर खुश है, तो यह राम जी का ही चमत्कार है। गौर से देखने से उसने लगाने लगा कि फिर भी कण-कण की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। किन्तु भी

वह रोजाना था कि अब नए जमाने की अर्थव्यस्था में सेल्फ़ी प्वाइंट भी बहुरूपी हो गया। उसके बाल में खुदा ने तम राम नजर आने लगा। कभी उसे लगा कि राम जी खुद पूछ रहे हैं कि हे भक्त सेल्फ़ी ले लो। तभी पीछे से एक आवाज ने उसे चौंका दिया। भारत के पहले सेल्फ़ी प्वाइंट – अंतिम सारा लेलो, ‘हे राम !’ कहा। गिरि हुए सेल्फ़ी प्वाइंट के ऊपर से गुजर कर लोग ‘जय श्रीराम’ का नारा लगा रहे थे। बुद्धिजीवी ने सेल्फ़ी प्वाइंट को उठाया। वह लगभग जर्जर हालत में खींचा जा रहा था। बुद्धिजीवी ने सेल्फ़ी प्वाइंट से उसके अनुभव के बारे में पूछा, तो कराहते हुए कहने लगा, ‘लेकिन यह खींचने से अधिक प्राण प्रतिष्ठित है, देश में यह खींचती सेल्फ़ी प्वाइंट को ही कहीं अधिक।’

निर्मल असं

विद्या

अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष बाबू ने कोलकाता के रास्तों का अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम कर दिया था। उनका झुकाव सांसारिक धन-वैभव या पदवी की ओर नहीं था। मित्रानुग्रह उन्हें सैन्यीय कहकर पुकारते थे। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर वालों ने विलायत में पढ़ने के लिए इस आशा से भेजा था कि आईसीएस की उच्च परीक्षा पास करके बड़ी सरकारी नौकरी करेंगे और परिवार की समृद्धि वह यश की रक्षा करेंगे, किंतु इसे छेड़कर वह क्रांतिकारी बनें।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन सर्वोच्च आदर्श और शक्ति के लिए संघर्ष से भरा रह चुका है। यह ऐसे नैजवाण युवा की कहानी है जो हर भारतीय के लिए संघर्ष और सफलता की राह का अनुभव करती है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसकी कल्पना समाज के महापुरुषों के बिना अधूरी है। ऐसे महापुरुषों में नेताजी अपनी प्रतिभा से समाज को अजादी दिलवाने चाहते थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसे फौज खड़ी कर दी थी जिसके मुख से एक ही नारा निकलता था 'जय हिंद' का। भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में क्रांतिकारी आंदोलन की अपनी लड़ाई की भूमिका निभाने में वह सफल राये और उनकी आंखों के सामने एक ही स्वप्न था भारत को आजाद करना है। सुभाष चंद्र बोस अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत २० में चल रहे असहयोग आंदोलन से की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता हासिल की। 20 जुलाई 1921 को उनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुई। लेकिन वैचारिक सामानता न होने के कारण उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे उनके अंदर असीम साहस अंतर्देशीय शक्ति और अनूठी संकल्प शक्ति का अनंत प्रवाह विद्यमान था।

वर्ष 1921 में अपने क्रांतिकारी विचारों

और गतिविधियों का संचालन करने के कारण पहली बार छह माह जेल जाना पड़ा। इसके बाद दो नये यात्राओं, अंग्रेजी अत्याचारों और सत्याग्रहों को शेराने का सिलसिला चल निकला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें न्याय्यर बार जेल जाना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा कई बार लंबे समय तक जेल भरादों भी रखा गया। लेकिन सुभाष चन्द्र बोस अपने इरादों से कभी भी टस से नस नहीं हुए। इसके लिए उन्होंने कई बार अंग्रेजों की आंखों में पलक डाली और अंग्रेजी शिकंजे से निकल भागे। 1939 में गांधीजी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। एक सप्ताह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत की आजादी में योगदान पर प्रकाश डाला गया है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी जिनमें 6 बेटियाँ और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र उनकी नौवाँ संतान और पाँचवाँ बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरतचंद्र से था। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेरेंशॉ कॉलेज में पूरी की। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसीडेन्सी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिप्लि लि सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड में गये। बोस को इंग्लैंड के कैब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया।

अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, किंतु उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों का समाचार पाकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट

आए। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का



A painting of a man in a green military uniform with a red sash and medals, standing against a blue sky with clouds. The text "JAI HIND" is written in red at the top.

उनका मकसद एक है, यानी देश की आजादी। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। बाद के दिनों में गांधी जी के लगतातर वैचारिक विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनेक महापुरुष हुए हैं। ऐसी ही महान विभूतियों में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने नेताजी को देशभक्ति का देशभक्त कहा था।

स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले सुभाष चंद्र बोस जब भारत आए तो रविंद्र नाथ टैगोर के कहने पर सबसे पहले गांधी जी से मिले थे। गांधी जी से पहली मुलाकात मुंबई में 20 जुलाई 1921 को हुई थी। गांधी जी की सलाह पर सुभाष कोलकाता में दास बाबू के साथ मिलकर आजादी के लिए प्रयास करने लगे। जब दास बाबू कोलकाता के महापौर थे, तब उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया था। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष बाबू ने कोलकाता के रास्तों का अंग्रेजी नाम बदलकर भारतीय नाम कर दिया था। उनका झुकाव सांसारिक धन-वैभव या पदवी की ओर नहीं था। मित्राण उन्हें संन्यासी कहकर पुकारते थे। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर वालों ने विलायत में पढ़ने के लिए इस आशा से भेजा था कि सुभाष आईसीएस की उच्च परीक्षा पास करके बड़ी सरकारी नौकरी करेंगे, फिर परिवार की समृद्धि एवं यश की रक्षा करेंगे, किंतु जिस समय वह विलायत में थे, उसी समय अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने भारत आकर अंग्रेजों के खिलाफ अपना क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। यही वजह है कि भारत 1947 में आजाद हो गया। आज सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान भारतीयों को आज भी याद है। उनकी रहस्यमयी मृत्यु से देश स्तब्ध हो गया था।

प्रो. मनोज डोगरा

प्रो. मनोज डोगरा

बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री पेश करती है इकोनमिक सर्वे, जानिए आखिर क्यों होता है यह जरूरी

परिवहन विशेष न्यूज

Budget 2024-25 1 फरवरी 2024 को केंद्र वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेगी। इस साल चुनाव के बाद यूनियन बजट पेश किया जाएगा। हर साल बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री Economic Survey पेश करती है। चलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि इकोनमिक सर्वे क्या होता है और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है ?

नई दिल्ली। 11 फरवरी 2024 को मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। इस बार केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेगी। इस साल चुनाव होने वाले हैं इस वजह से चुनाव के बाद यूनियन बजट पेश होगा। इसका मतलब है कि इस साल 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हर साल बजट से एक दिन पहले केंद्र वित्त मंत्री इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश करते हैं। चलिए, आज हम आपको इस सर्वे के बारे में बताते हैं।

क्या है इकोनॉमिक सर्वे

देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे हर साल बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा इसमें सरकार के विकास कार्यक्रमों की समरी भी पेश की जाती है। इसमें सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला जाता है। आसान शब्दों में समझे तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का एक टूटिकोण पेश किया जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 1950-51 में पेश किया गया था। इसे



बजट के साथ ही पेश किया गया था। वर्ष 1964 के बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया और तब से बजट से एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है।

क्यों जरूरी होता है आर्थिक सर्वेक्षण

इकोनॉमिक सर्वे इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें सरकार कृषि, सर्विस, उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे बाकी सेक्टर के प्रदर्शन करते हैं। यह इन सेक्टर के आर्थिक विश्लेषण में मदद करता है। इसके अलावा यह आने वाले वित्तीय वर्ष में आर्थिक रणनीति को तैयार करने में भी मदद करता है। इस सर्वे से आर्थिक विकास में आ रही बाधाओं के बारे में पता लगाया जा सकता है।

कैसे तैयार होता है इकोनॉमिक सर्वे

इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। इन्हें पीएम द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन हैं। अगर आप भी

इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे

‘www.indiabudget.gov.in/economic_survey’ पर जाकर डाउनलोड कर

सकते हैं। आपको बता दें कि संसद में पेश होने के बाद ही यह पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

राम मंदिर को लेकर अमूल का डूडल हुआ वायरल, 1 लाख से ज्यादा आए लाइक और कमेंट

अयोध्या राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर अमूल (Amul) ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर पेश किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को दिखाया है जिसमें अमूल का क्लासिक डूडल भी शामिल है।

नई दिल्ली। डेयरी ब्रांड अमूल (Amul) ने इंस्टाग्राम (Instagram) पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में राम मंदिर की तस्वीर है। इस पोस्ट में दिखाया गया है कि राम मंदिर के समारोह में अमूल की क्लासिक डूडल अमूल गल भी शामिल है। अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पोस्ट पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया एक अरब आशाओं के मंदिर की तस्वीर। इस फोटो में अमूल गल नंगे पैर राम मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। अमूल ने इस पोस्ट पर लिखा सामयिक अयोध्या मंदिर का उद्घाटन।

वायरल हुई अमूल की पोस्ट

अमूल ने राम मंदिर को लेकर जो पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की वह कुछ घंटे में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पोस्ट को 1 लाख से ज्यादा लोग ने लाइक किया। वहीं, कई लोगों ने इस पोस्ट पर जय श्री राम का कमेंट किया। कुछ लोगों ने दिल वाले इमोजी भी शेयर किये।

सेविंग अकाउंट के साथ ग्राहकों को मिलते हैं ये बेनिफिट्स, जान लें तो फायदे में रहेंगे आप



सेविंग के लिए बैंक अकाउंट बेस्ट ऑप्शन में से एक है। देश में लगभग सभी के पास बैंक अकाउंट है। हालांकि कई लोग यह नहीं जानते हैं कि वह जो सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं उस पर बैंक उन्हें कई तरह के लाभ भी दे रहा है। चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि बैंक ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर क्या लाभ देता है।

नई दिल्ली। सेविंग करने के लिए कई लोग बैंक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पैसे सिक्योर होते हैं उसी के साथ बैंक भी इस राशि पर ब्याज देती है। सेविंग अकाउंट पर बैंक इंटररेस्ट के साथ कई और लाभ भी देते हैं। कई लोग इस लाभ के बारे में नहीं जानते हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पर क्या लाभ मिलता है।

पैसे सिक्योर

जब भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको पैसे की टेशन नहीं होती है। यहां आपके पैसे पूरी तरह से सिक्योर होते हैं।

इन्टरेस्ट

सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट राशि पर भी बैंक ब्याज देता है। सभी बैंकों की ब्याज दर अलग होती है।

फाइनेंशियल डिस्प्लेन

घर पर केश रखने से ज्यादा अच्छा होता है कि बैंक में रखें। यह एक वित्तीय आदत भी है। बैंक में राशि रखने से फिजूल खर्च नहीं होती है और साथ ही बचत की जाती है। वैसे तो इन सेविंग का इस्तेमाल आपत स्थिति में करना चाहिए।

सेविंग एक तरह से आपके वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है।

उदाहरण के तौर पर अगर आप बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो आप उसके लिए सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। आप अगर अपनी बाइक के लिए हर महीने एक फिक्स अमाउंट सेव करते हैं तो जल्द ही आप बाइक खरीद सकते हैं।

लोन

अगर किसी काम के लिए आपको लोन चाहिए तब भी सेविंग अकाउंट आपको मदद करता है। बैंक आपके सेविंग और बैंक ट्रान्जेक्शन के आधार पर लोन देता है। इसके अलावा अगर आपने लोन लिया होता है तो आप बैंक आपके अकाउंट में जमा राशि का इस्तेमाल ईएमआई के लिए कर सकती है।

आईटीआर

देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। आपकी इनकम आपके सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होती है, ऐसे में आप अपने सालाना इनकम की गणना आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप अपने इनकम प्रूफ के लिए बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं।

तुरंत पेमेंट की सुविधा

अगर आपको तुरंत कहीं केश की जरूरत पड़ती है तो आप डेबिट कार्ड के जरिये यह सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। डेबिट कार्ड, यूपीआई के जरिये आप आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं।

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ कर सकती है सरकार

सरकार अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपये तक कर सकती है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2023 तक 20 लाख करोड़ रुपये के कृषि-ऋण लक्ष्य का लगभग 82 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। उक्त अवधि में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के बैंकों द्वारा लगभग 16.37 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है।



वर्तमान में सरकार सभी वित्तीय संस्थानों के लिए तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण पर दो प्रतिशत की छूट प्रदान करती है। इसका मतलब है कि किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख रुपये का कृषि ऋण मिल रहा है। समय पर भुतान करने वाले

किसानों को प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट भी प्रदान की जा रही है। किसान दीर्घकालिक ऋण भी ले सकते हैं, लेकिन ब्याज दर बाजार के अनुसार होती है। सूत्रों के अनुसार, कृषि ऋण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और सरकार छूटे हुए पात्र किसानों की पहचान करने और उन्हें ऋण

लगभग 82 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है। उक्त अवधि में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के बैंकों द्वारा लगभग 16.37 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। कृषि ऋण वितरण चालू वित्त वर्ष में भी लक्ष्य से अधिक रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल कृषि ऋण वितरण 21.55 लाख करोड़ रुपये था, जो इसी अवधि के लिए रखे गए 18.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक था।

केसीसी से 7.34 करोड़ किसानों ने कर्ज प्राप्त किया।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से 7.34 करोड़ किसानों ने कर्ज प्राप्त किया। 31 मार्च 2023 तक करीब 8.85 लाख करोड़ रुपये बकाया था। 2019 एनएसएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का प्रतिशत 50.2 प्रतिशत है। जिसमें से 69.6 प्रतिशत बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों से लिया गया था। एनएसएस रिपोर्ट को देखते हुए, सूत्रों ने कहा कि अभी भी कृषि परिवारों का एक बड़ा वर्ग है जिनके पास संस्थागत ऋण तक पहुंच नहीं है। सरकार ऐसे लोगों को औपचारिक क्रेडिट नेटवर्क के तहत लाने का लक्ष्य बना रही है।

कर में उछाल से सामाजिक योजनाओं का बजट बढ़ाने में मिलेगी मदद, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

कर में उछाल से सरकार को आगामी अंतरिम बजट में किसानों और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करने में मदद मिलेगी। खबर के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आय व कापॉरेट कर संग्रह में उछाल दिख रहा है और कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है।



और कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान से लगभग एक लाख करोड़ रुपये अधिक होने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर से 18.23 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। 10 जनवरी तक

14.70 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह हो चुका है, जो बजट अनुमान का 81 प्रतिशत है।

केंद्रीय जीएसटी राजस्व में होगी बढ़ोतरी

49,000 करोड़ रुपये की कमी रहेगी। केंद्र का सकल कर राजस्व 33.6 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 60,000 करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है।

रेंटिंग एजेंसी इक्रा ने किया ये दावा

रेंटिंग एजेंसी इक्रा ने अपनी अंतरिम बजट रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष कर और जीएसटी संग्रह के कारण सकल कर राजस्व 11 प्रतिशत बढ़ेगा। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संग्रह में भी वृद्धि की संभावना है। इस कर उछाल ने सरकार को मनरेगा, ग्रामीण सड़कों, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित करने की गुंजाइश दी है।

चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। डेलाइट इंडिया के पार्टनर संजय कुमार का कहना है कि फिलहाल सरकार के पास कुछ निश्चित राजकोषीय गुंजाइश है और वे उसे खर्च करना चाहेंगे।

कुमार ने कहा कि 2024-25 के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचा, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। चालू वर्ष के लिए बजट का आकार 40 लाख करोड़ रुपये था और अगले वर्ष यह 10 प्रतिशत बढ़कर 43-44 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है।

पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम पर मिलता है Tax Benefit का लाभ?



Mahila Samman Savings Certificate (MSSC) देश के सभी टैक्सपेयर्स को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में कई स्कीम पर करदाता को टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना (Mahila Samman Bachat Yojana) पर भी टैक्स कटौती का लाभ मिलता है या नहीं। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

स्कीम पर मिलता है टैक्स बेनिफिट ?

इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80 सी (Income Tax Act 1961 80C) के तहत टैक्स बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। हालांकि, योजना में मिल रही ब्याज पर टैक्स देना होता है। इसका मतलब कि इस स्कीम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है। इंटररेस्ट पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है। यह स्कीम एफडी (FD) की तरह ही काम करता है। उदाहरण के तौर पर अगर इस स्कीम में आप 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी के बाद 2.32 लाख रुपये मिलेगा।

इस स्कीम को आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (Pan Card) अपलोड करना होगा।

अब इस स्कीम का लाभ देश के कई बैंक में मिल रहा है।

कितना कर सकते हैं निवेश

इस स्कीम में कम से कम 1,000 रुपये तक का निवेश करना होता है। वहीं अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ही निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही महिला सेविंग अकाउंट है और आप दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उन दो अकाउंट के बीच 3 महीने का गैप होना चाहिए। महिला सेविंग अकाउंट खोलने के 1 साल के बाद इसमें से 40 फीसदी राशि निकाली जा सकती है।

